

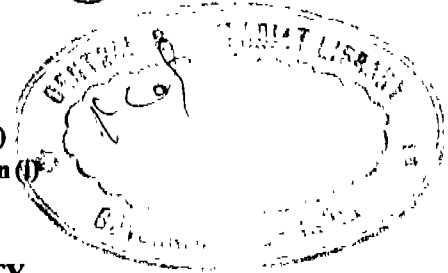


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 315]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जून 21, 2001/ज्येष्ठ 31, 1923

No. 315]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 21, 2001/JYAISTHA 31, 1923

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2001

सं. 30/2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन. टी.)

सा. का. नि. 444(अ).—केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 का उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई थीं या जिनका किए जाने से लोप किया गया था, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सं. 2) नियम, 2001 है।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) ये 1 जुलाई, 2001 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ—इन नियमों में, जब तक कि उक्त विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो—

(क) "अधिनियम" से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 अभिप्रेत है ;

(ख) "निर्धारण" से निर्धारिती द्वारा किया गया शुल्क का स्वःनिर्धारण अभिप्रेत है और नियम 10 के अधीन अनन्तिम निर्धारण भी है ;

(ग) "निर्धारिती" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो निर्धारित किए गए शुल्क के संदाय के लिए दायी है और इसके अंतर्गत उत्पाद शुल्क्य माल का कोई उत्पादक या विनिर्माता अथवा ऐसे प्राइवेट भांडागार का रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति भी है जिसमें उत्पाद शुल्क्य माल भंडारित है ;

(घ) "बोर्ड" से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अधीन गठित उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ङ) "शुल्क" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन संदेय शुल्क अभिप्रेत है ;

(च) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(छ) "समुचित प्ररूप" से बोर्ड द्वारा अधिसूचित उचित प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ज) “भांडागार” से नियम 15 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्थान या परिसर अभिप्रेत है;

(झ) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में क्रमशः दिए गए हैं।

3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों की नियुक्ति और अधिकारिता—(1) बोर्ड अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को जिसे वह उचित समझे, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी नियुक्त कर सकेगा अथवा ऐसे अधिकारी को इन नियमों द्वारा प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत कर सकेगा।

(2) बोर्ड, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजन के लिए मुख्य आयुक्त, आयुक्त या आयुक्ता (अपील) की अधिकारिता विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी अपने अधीन किसी अन्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को अधिनियम अथवा इन नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

4. शुल्क की वसूली—(1) नियम 7 के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति जो कोई उत्पाद शुल्क माल उत्पादित या विनिर्मित करता है या जो किसी भांडागार में ऐसा माल भंडारित करता है, ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क या शुल्कों का इन नियमों में विहित रीति से संदाय करेगा और कोई भी ऐसा उत्पाद शुल्क माल जिस पर किसी शुल्क या शुल्कों का संदाय किया जाता है, यथास्थिति, ऐसे किसी स्थान से जहां वह उत्पादित या विनिर्मित किया जाता है या किसी भांडागार से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क का संदाय नहीं कर दिया गया है :

परंतु यह भी कि किसी फुटकर कर्मकार द्वारा उत्पादित या विनिर्मित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय 62 के अंतर्गत आने वाले माल को, उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क के संदाय के बिना हटाया जा सकेगा यदि ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क का संदाय उपनियम (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा इस प्रकार संदाय किया गया है मानों ऐसा माल नियम 9 के अधीन रजिस्ट्रीकृत उसके परिसर से ऐसे माल के हटाए जाने की तारीख को उसके द्वारा उत्पादित या विनिर्मित किया गया है।

स्पष्टीकरण :—यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां ऐसे व्यक्ति ने उपनियम (3) के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क अदा करने के लिए जॉब कार्यकर्ता को प्रधिकृत किया हो, ऐसा शुल्क जॉब कार्यकर्ता द्वारा उसके रजिस्ट्रीकृत परिसर से ऐसे माल के निकासी के दिन किया जायेगा।

(2) उप-नियम (1) में, किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी खांडसारी चीनी कारखाने द्वारा उत्पादित सीरे की बाबत, ऐसा व्यक्ति जो खांडसारी चीनी कारखाने में उत्पादित सीरे को सीधे कारखाने से अन्यथा किसी वस्तु के विनिर्माण के लिए भले की वह उत्पाद शुल्कीय हो अथवा नहीं, उपयोग हेतु उपाप्त करता हो, ऐसे सीरे पर उद्ग्रहणीय शुल्क का उमी रीति से संदाय करेगा मानों ऐसा सीरा उपाप्तकर्ता द्वारा उत्पादित किया गया हो।

(3) उपनियम (1) में दिये किसी प्रावधानों के बावजूद, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के पास, जो फुटकर कर्मकारों द्वारा उसकी बाबत उत्पादित या विनिर्मित, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय 62 के अंतर्गत आने वाले माल को प्राप्त करता है, ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क या शुल्कों का संदाय करने का इस प्रकार विकल्प होगा मानों ऐसा माल ऐसे व्यक्ति द्वारा, ऐसे समय पर ऐसी रीति में जो इन नियमों के अधीन विहित की जाए, विनिर्मित किया गया है चाहे ऐसे शुल्क या शुल्कों का संदाय बंध-पत्र द्वारा या अन्यथा प्रतिभूत किया गया है।

परंतु यह कि ऐसे व्यक्ति किसी जॉब कार्यकर्ता को ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क संदाय करने के लिए, अपनी बाबत, प्राधिकृत करता है तथा ऐसा प्राधिकृत जॉब कार्यकर्ता सारी देनदारियाँ अदा करने एवं इन नियमों के सारे प्रावधानों को मानने का उपक्रम देता है।

स्पष्टीकरण I :—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “जॉब कार्यकर्ता” पद से जॉब कर्मकार को प्रदाय की गई कच्ची सामग्री, पुर्जों, संघटकों या अर्धसज्जित माल का प्रसंस्करण या उस पर कार्य करना अभिप्रेत है जिससे कि कोई भागतः या पूर्णतः प्रक्रिया पूरी हो सके जिसके परिणामस्वरूप उक्त प्रथम अनुसूची के अध्याय 62 में आने वाले, किसी वस्तु का विनिर्माण या परिसज्जा या कोई संक्रिया हों जो उपर्युक्त प्रक्रिया के लिए आवश्यक हो। शंका निर्मूलन के लिए यह और स्पष्ट किया जाता है कि जॉब कार्यकर्ता किसी प्रसंस्करण का कोई भाग, जो उक्त माल के विनिर्माण के लिए आवश्यक हो, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कर सकता है, लेकिन उक्त माल को विनिर्माण पूर्ण करने के लिए वापस अपने कारखाने में लाना चाहिए।

स्पष्टीकरण II :—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, कारखाने में बने उत्पाद शुल्क माल जिन्हें या तो उसी रूप में या और प्रौसेसिंग करने के उपरांत, किसी अन्य माल के विनिर्माण में उक्त कारखाने में प्रयोग किया जाता है तब उनकी निकासी उक्त कारखाने में ऐसे प्रयोग से तुरंत पहले की समझी जायेगी।

5. शुल्क निर्धारण की तारीख—(1) किसी उत्पाद शुल्कीय माल को लागू होने वाले शुल्क की दर उस तारीख को प्रवृत्त दर होगी जब ऐसा माल, यथास्थिति, कारखाने या भांडागार से हटाया जाता है।

(2) खांडसारी सीरे की दशा में शुल्क की दर ऐसे सीरे के उपाप्तकर्ता के कारखाने में ऐसे सीरे की प्राप्ति की तारीख को प्रवृत्त दर होगी।

स्पष्टीकरण :—यदि कोई उत्पाद शुल्कीय माल का उपयोग कारखाने में किया जाता है तो ऐसे माल को हटाए जाने की तारीख से वह माल ऐसे उपयोग के लिए जारी किए जाने की तारीख अभिप्रेत है।

(3) किसी फुटकर कर्मकार द्वारा उत्पादित या विनिर्मित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय 62 के अंतर्गत आने वाले माल की दशा में, शुल्क की दर, नियम 4 के उपनियम (3) में दिए गए व्यक्ति द्वारा नियम 9 के अधीन रजिस्ट्रीकृत परिसरों से ऐसे माल के हटाने की तारीख को लगने वाली दर होगी।

6. शुल्क का निर्धारण—(1) विनिर्माता या भांडागार का स्वामी, सिगरेटों की बाबत के सिवाय, किसी उत्पाद शुल्कीय माल पर संदेय शुल्क का निर्धारण करेगा।

परन्तु कि सिगरेट के मामले उत्पाद शुल्क अधीक्षक या निरीक्षक, निर्धारिती द्वारा निकासी से पहले, शुल्क का निर्धारण करेगा।

7. (1) अनन्तिम निर्धारण—जहां निर्धारित उत्पाद शुल्कीय माल का मूल्य निर्धारण करने में असमर्थ है या उस पर लागू शुल्क की दर का निर्धारण करता है तो वह उचित अधिकारी से लिखित में अनन्तिम आधार पर शुल्क का संदाय करने के लिए कारण देते हुए अनुरोध कर सकेगा।

(2) समुचित अधिकारी अनन्तिम आधार पर ऐसी दर पर या मूल्य पर जो उचित अधिकारी द्वारा उपदर्शित किया जाए, निर्धारण किए जाने के लिए शुल्क अनुज्ञात कर सकेगा और निर्धारण दिए जाने के अधीन रहते हुए वे निर्धारितियों पर आबद्ध होंगे। समुचित अधिकारी निर्धारिती से अनन्तिम रूप से निर्धारित पाए गए शुल्क की रकम और अनन्तिम रूप से निर्धारित शुल्क के बीच किसी कमी, यदि कोई हो का संदाय करने के लिए निर्धारिती को आबद्ध करने हेतु ऐसी रकम की प्रतिभूति या प्रतिभू के साथ बंधपत्र निष्पादित करने के लिए मांग कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे।

(3) समुचित अधिकारी निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए यथा अपेक्षित सुसंगत सभी जानकारी उपलब्ध करा दिए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र एवं किसी भी दशा में आदेश के संप्रेक्षण की तारीख के 6 महीने के अंदर, अंतिम रूप से माल का निर्धारण करेगा :

परन्तु कि इस उपनियम में दी गई अवधि, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता द्वारा समुचित कारण बताए जाने पर एवं लिखित आदेश द्वारा, आगे 6 महीने तक और बढ़ाई जा सकेगी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य समाहर्ता द्वारा यह अवधि यथोचित समय तक बढ़ाई जा सकेगी।

(4) निर्धारिती, केन्द्र सरकार को ऐसी राशि, जो उपनियम (3) के अधीन पारित अंतिम निर्धारण पर देय होती है, पर 24 प्रतिशत वार्षिक दर से, जिस महीने में शुल्क देय निर्धारण होता है, उस महीने से अगले महीने की पहली तारीख से राशि की अदायगी की तारीख तक ब्याज देगा।

(5) केन्द्र सरकार, उपनियम (6) का पालन करते हुए, निर्धारिती को ऐसी राशि, जो उपनियम (3) के अधीन पारित अंतिम निर्धारण पर देय होती है, पर 15 प्रतिशत वार्षिक दर से, जिस महीने में शुल्क देय निर्धारण होता है, उस महीने से अगले महीने की पहली तारीख से राशि की अदायगी की तारीख तक ब्याज देगा।

(6) शुल्क वापसी की कोई रकम जो उपनियम (3) में निर्धारित होती है उपभोक्ता वेलफेयर फंड को दी जायेगी :

परन्तु कि शुल्क वापसी की रकम फंड को दिए जाने के बजाय आवेदक को दी जायेगी यदि ऐसी रकम :—

(क) विनिर्मिता द्वारा दिए गए उत्पाद शुल्क जिसका भार उसने किसी अन्य व्यक्ति को न दिया हो, अथवा

(ख) खरीदार द्वारा वहन किए गए उत्पाद शुल्क, जिसका भार उसने किसी अन्य व्यक्ति को न दिया हो, से संबंधित है।

8. संदाय की रीति—(1) प्रत्येक मास के पहले पक्ष के दौरान कारखाने या भांडागार से हटाए माल पर शुल्क का संदाय उस मास की 20 तारीख तक किया जायगा और उक्त मास के दूसरे पक्ष के दौरान कारखाने या भांडागार से हटाए गए माल पर शुल्क का संदाय अगले मास की 5 तारीख तक किया जाएगा :

परन्तु मार्च के दूसरे पक्ष के दौरान हटाए गए माल की दशा में शुल्क का संदाय 31 मार्च तक किया जाएगा :

परन्तु यह और कि किसी अधिसूचना के अधीन वित्तीय वर्ष में निकामियों के मूल्य पर आधारित छूट प्राप्त करने वाले विनिर्माता की दशा में किसी कलेण्डर मास के दौरान निकासी किए गए माल पर शुल्क का संदाय उत्तरवर्ती मास की 15 तारीख तक किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि शुल्क दायित्व केवल तभी उन्मोचित किया गया समझा जाएगा जब संदेय रकम केन्द्रीय सरकार के खाते में विनिर्दिष्ट तारीख तक जमा कर दी जाती है।

(2) उत्पाद शुल्क का उत्पाद शुल्कीय माल पर इन नियमों के प्रयोजन के लिए संदाय किया गया समझा जाएगा और ऐसे शुल्क का मुजरा किसी भी नियम के अधीन उपबंधित रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

(3) यदि विनिर्माता शुल्क की रकम का शोध्य तारीख तक संदाय करने में असफल रहता है तो वह बकाया रकम और उसके साथ बकाया रकम शोध्य तारीख के पश्चात् पहले दिन से आरंभ होने वाली और बकाया के वार्षिक संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा।

(4) यदि विनिर्माता—

- (i) उस तारीख से जिसको किसी वित्तीय वर्ष में किस्त शोध्द नीति, 30 दिन की अवधि के भीतर किसी 1 किस्त का पूरा संदाय करने में ; या
- (ii) किसी वित्तीय वर्ष में तीसरी बार क्रमशः या अन्यथा नियत तारीख तक किस्त का संदाय करने में असफल रहता है तो विनिर्माता इस नियम के अधीन किस्तों के बकाया का सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित किसी आदेश की संसूचना के आदेश की तारीख से प्रारंभ होने वाली दो मास की अवधि के लिए संदाय करने या ऐसी तारीख तक संदाय करने जिसको सभी शोध्दों का संदाय कर दिया जाता है, जो भी बाद की हो, संदाय करने की सुविधा को समग्रहरित कर देगा और इस अवधि के दौरान विनिर्माता से चालू खाते में नाम डालकर प्रत्येक पारेषण के लिए उत्पाद शुल्क का संदाय करने की अपेक्षा की जाएगी और किसी असफलता की दशा में यह समझा जाएगा कि ऐसा माल शुल्क का संदाय किए बिना निकासी किया गया है और इन नियमों में उपबंधित परिणाम और शास्तियां उसे भोगनी पड़ेगी।

9. कतिपय व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण—(1) प्रत्येक व्यक्ति जो उत्पाद शुल्क माल का उत्पादन, विनिर्माण, व्यापार करता है, प्राइवेट भंडागार कक्ष या भंडागार रखता है या अन्यथा उपयोग करता है, तो वह रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेगा।

परन्तु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 की नियम 174 के अधीन लिया गया पंजीकरण इस उपनियम के अधीन लिये गए पंजीकरण के समान ही इन नियमों के प्रयोजन के लिए वैध होगा।

(2) बोर्ड अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए जो ऐसी अधिसूचना में विहित की जाएं, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों में से व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग विहित कर सकेगा जिनको ऐसा रजिस्ट्रीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है।

(3) उपनियम (1) के तहत रजिस्ट्रीकरण बोर्ड द्वारा अधिसूचित शर्तों सीमाओं एवं प्रक्रियाओं के अधीन होगा।

10. दैनिक स्टॉक लेखा—(1) प्रत्येक विनिर्माता पठनीय रीति में उचित अभिलेख रखेगा जिनमें विनिर्मित माल के विवरण, आरंभिक अतिशेष, विनिर्मित मात्रा, हटाई गई मात्रा, माल की सूची, निर्धारणीय मूल्य, संदेय शुल्क की रकम और वास्तव में संदेय शुल्क की रकम के संबंध में विशिष्टियों को दर्शित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक लेखा रजिस्ट्र के पहले पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ को विनिर्माता या उसके अधिकर्ता द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित किया जाएगा।

(3) ऐसे सभी अभिलेखों को उस वित्तीय वर्ष के पश्चात् जिसके संबंध में वे अभिलेख हैं, पांच वर्ष तक सुरक्षित रखा जाएगा।

11. बीजक पर परिदत्त किया जाने वाला माल—(1) किसी भी कारखाने या भंडागार से कोई भी उत्पाद शुल्कीय माल उस कारखाने के स्वामी या उसके प्राधिकृत अधिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित बीजक के अधीन ही परिदत्त किया जाएगा। आगे सिगरेटों की दशा में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक, सिगरेटों को कारखाने से हटाए जाने से पूर्व ऐसे प्रत्येक बीजक पर प्रति हस्ताक्षर करेगा।

(2) बीजक क्रमशः संख्याक के साथ होगा एवं इसके अन्तर्गत प्रजीकरण संख्या, माल का विवरण, वर्गीकरण, निकासी के समय एवं तारीख, शुल्क की दर मात्रा और मूल्य तथा उस पर संदेय शुल्क दिया होगा।

(3) बीजक निम्नलिखित रीति में तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा :—

- (i) मूल प्रति को मूल प्रति के रूप में अंकित किया जाएगा;
- (ii) दूसरी प्रति को परिवाहक के लिए दूसरी प्रति के रूप में अंकित किया जाएगा ;
- (iii) तीसरी प्रति को निर्धारिती के लिए तीसरी प्रति के रूप में अंकित किया जाएगा।

(4) एक बार में बीजक की एक से अनधिक प्रति का उपयोग नहीं किया जाएगा, जब तक कि किसी निर्धारिती के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में, यथास्थिति, सहायक आयुक्त या उपायुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा अन्यथा अनुज्ञात न कर दिया गया हो।

(5) यथास्थिति स्वामी या कार्यकारी भागीदार या प्रबंध निदेशक/कंपनी सचिव उपयोग में लाने से पूर्व बीजक की प्रत्येक वर्णी को अधिपमाणित करेगा।

(6) बीजक का क्रम संख्यांक उपयोग में लाने से पूर्व रेंज अधीक्षक संसूचित किया जाएगा।

12. विवरणी.—प्रत्येक निर्धारिती केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को प्रत्येक महीने के माल के उत्पादन और हटाने की विवरणी तथा अन्य सुसंगत विशिष्टियां इस निर्मित विनिर्दिष्ट समुचित प्ररूप महीने के समाप्त होने के दस दिन में देगा :

परन्तु निकासी के मूल्य के आधार पर दी जाने वाले शुल्क में छूट की अधिसूचना का लाभ लेने वाले निर्धारित के मामले में, निर्धारित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को प्रत्येक तिमाही के दौरान माल के उत्पादन और हटाने की विवरणी तथा अन्य सुसंगत विशिष्टियां इस निर्मित विनिर्दिष्ट समुचित प्ररूप तिमाही के समाप्त होने के बीस दिन में देगा :

13. **दियासलाइयों पर शुल्क**—दियासलाइयों पर शुल्क की दर के समुचित मूल्य की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की स्टैम्प को प्रत्येक डिब्बी या बुकलेट पर लगाकर संदत्त की जाएगी और जहां ऐसी डिब्बियां या बुकलेट पैकेटों में जारी की जाती हैं वहां प्रत्येक पैकेट को विनिर्माता द्वारा वितरण की न्यूनतम इकाई के रूप में हिसाब में लिया जाता है वहां पैकेटों में की डिब्बियों के वर्ग पर विनिर्माता के व्यापार का लेबल और कोई चिन्ह स्पष्ट रूप से लगा होगा।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टैम्पों को उपाप्त करने और उत्पादन के अभिलेखों को बनाए रखने तथा दियासलाई को हटाने की प्रक्रिया।

14. **केन्द्रीय उत्पाद शुल्क**—स्टैम्प उपाप्त करने की प्रक्रिया और दियासलाई के उत्पादन और उनके हटाए जाने के लिए अभिलेख रखना-बोर्ड, अधिसूचना द्वारा उपाप्त करने का लेखा रखने की प्रक्रिया और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टैम्पों के ध्वन्य और दियासलाई के उत्पादन, भंडार, नियंत्रण, हटाए जाने और उन पर शुल्क का संदाय करने की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

15. **शुल्क के संदाय की विशेष प्रक्रिया**—(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे माल को अधिसूचित कर सकेगा जिसकी बाबत विनिर्माता के पास ऐसे तथ्यों के आधार पर ऐसे माल के उत्पादन से सुसंगत हों, ऐसी दर पर जो इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित की जाए, उत्पाद शुल्क का संदाय करने का विकल्प होगा।

(2) केन्द्रीय सरकार वह रीति भी जिसमें विशेष प्रक्रिया का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जाएगा, शुल्क के संदाय की रीति, उपशमन, यदि कोई हो, जो किसी अवधि के दौरान कारखाने परिसर के मददे अनुज्ञात किया जाएगा, अधिसूचित कर सकेगी।

16. **कारखाने में वापस आए माल पर शुल्क का मुजरा**—(1) जहां ऐसा माल जिसपर उसके हटाए जाने के समय शुल्क संदत्त की गई थी किन्तु, पुनः बनाए जाने, परिष्कृत करने, सुधार करने या किसी अन्य कारण से कारखाने को तत्पश्चात् लौटाया जाता है वहां विनिर्माता अपने अभिलेख में ऐसी विवरणी की विशिष्टियां उपदर्शित करेगा और संदत्त शुल्क के कर के मुजरे का इस प्रकार हकदार होगा मानो ऐसा माल केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर नियमों के तीन निवेश के रूप में प्राप्त किया जाता है और उसका तदनुसार केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर मुजरे के रूप में उपयोग किया जाएगा।

(2) विनिर्माता ऐसे माल पर शुल्क का संदाय करने का अभिदायी होगा जिसे तत्पश्चात् साधारण रीति में इस प्रकार हटाया जाता है मानो उसे ऐसे विनिर्माता द्वारा विनिर्मित किया गया है और हटाया गया है इस बात पर ध्यान दिए बिना कि माल को उस रूप में हटाया गया है या चाहे उसे पुनः बनाने, परिष्करण या कोई अन्य प्रक्रिया जिसके अधीन माल तत्पश्चात् रूप में हटाए जाने के पूर्व था, विनिर्माण द्वारा हटाया गया समझा जाएगा या नहीं।

(3) यदि उपनियम (1) एवं उपनियम (2) में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करने में कोई कठिनाई आती है तब निर्धारित माल को, उत्पाद शुल्क समाहर्ता द्वारा रखे गए शर्तों के अधीन पुनः बनाए जाने, परिष्कृत करने, सुधार करने या किसी अन्य कारण से कारखाने को लौटा सकेगा एवं पुनः निकासी कर सकेगा।

17. **मुक्त व्यापार जोन या घरेलू टैरिफ क्षेत्र के लिए शतप्रतिशत निर्यात उन्मुख उपक्रम में किसी इकाई अथवा विशेष आर्थिक जोन में किसी इकाई द्वारा माल का हटाया जाना**—(1) जहां मुक्त व्यापार जोन या किसी शतप्रतिशत निर्यात की इकाई या किसी शतप्रतिशत निर्यात-उन्मुख इकाई अथवा विशेष आर्थिक जोन में किसी इकाई को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में किसी माल को हटाना है वहां इस प्रकार माल का हटाया जाना नियम 15 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करके किसी बीजक के अधीन चालू लेखा में विकलन द्वारा समुचित शुल्क के संदाय निकासी से पूर्व किया जाएगा जो इस प्रयोजन के लिए रखे जाने के लिए अपेक्षित होगा।

(2) ऐसी इकाई उत्पादन से संबंधित समुचित लेखा, माल का वर्णन, हटाए गए माल की मात्रा, संदत्त शुल्क को समुचित रूप में रखेगी और इस प्रकार हटाए जाने को बीजक में रखा जाएगा।

(3) इकाई उस मास के बंद होने के पश्चात् दस दिन के भीतर जिससे विवरणी संबंधित है घरेलू टैरिफ क्षेत्र में हटाए गए माल के बाबद इस प्ररूप में जो बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए विहित की जाए एक मासिक विवरणी फाइल करेगी।

18. **शुल्क की रिबेट**—जहां कोई उत्पाद शुल्कीय माल निर्यातित किया जाता है वहां केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उत्पाद शुल्क्य माल पर संदत्त शुल्क या उत्पाद शुल्क्य माल में प्रयुक्त सामग्री पर संदत्त शुल्क की रिबेंट अनुदत्त कर सकेगी। उक्त रिबेंट ऐसी शर्तों या सीमाओं के, यदि कोई हों, और ऐसी प्रक्रिया के पूरा किए जाने के अध्वधीन होगी जो इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

स्पष्टीकरण—निर्यात के अंतर्गत माल का रसद के रूप में जलयान पर लादना या किसी विदेशी पत्तन को जाने वाले जलयान पर लादने के प्रयोजन के भंडार करना या विदेश जाने वाले वायुयान को प्रदाय करना भी है।

19. **बिना शुल्क की अदायगी के निर्यात**—(1) कोई भी उत्पाद शुल्क्य माल विनिर्माता के कारखाने या भांडागार या किसी ऐसे अन्य परिसर से जो आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाए, शुल्क का संदाय किए बिना निर्यात किया जा सकेगा।

(2) कोई माल, उत्पादक या विनिर्माता के कारखाने अथवा भंडारगृह अथवा किसी अन्य परिसर से निर्यात किए जाने वाले माल के उत्पादन या विनिर्माण लिए, कि आयुक्त द्वारा अनुमोदित रीति से बिना शुल्क अदा किए निकासी की जा सकेगी।

(3) उपनियम (1) अथवा उपनियम (2) के अधीन निर्यात ऐसी शर्तों, रक्षोपायों या प्रक्रिया के अध्वधीन होगा जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विहित की जाए।

20. **भांडागार रसद**—(1) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उत्पादन के कारखाने से किसी भांडागार को किसी उत्पाद शुल्क के माल को हटाने की सुविधा का विस्तार शुल्क के संदाय के बिना या किसी ऐसे भांडागार से अन्य भांडागार को शुल्क के संदाय के बिना कर सकेगी।

(2) सुविधा ऐसी शर्तों (जिसमें शास्ति और ब्याज सम्मिलित हैं), सीमाओं (जिसमें उस अवधि की बाबत जिसके लिए माल भांडागार में रखा जा सकेगा) और उपायों तथा प्रक्रिया, जिसमें ऐसे माल के प्रेषण, हटाने, प्राप्ति, देनदारी और व्ययन से संबंधित विषय सम्मिलित हैं, जो इस निमित्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा विहित की जाए।

(3) उस माल पर शुल्क के संदाय के लिए उत्तरदायित्व जो उत्पादन के कारखाने से किसी भांडागार या एक भांडागार से अन्य भांडागार को हटाया जाता है, भांडागार के स्वामी पर होगा जब तक कि भांडागार के लिए प्रेषित माल उसके द्वारा प्राप्त नहीं कर लिया जाता है जिसमें माल का विक्रेता उसके द्वारा विक्रित माल पर शुल्क के संदाय के लिए दायी बना रहेगा।

(4) यदि भांडागारण या पुनः भांडागारण के लिए प्रेषित माल भांडागार में प्राप्त नहीं होता है तो शुल्क के संदाय का उत्तरदायित्व उम व्यक्ति पर होगा जिसने माल प्रेषित किया था।

21. **शुल्क की माफी**—जहां समाहर्ता को सम्यक रूप से यह संतुष्ट किया जाये कि माल, निकासी से पूर्व, खो गये हैं या प्राकृतिक कारण अथवा दुर्घटना में नष्ट हो गए हैं या विनिर्माता द्वारा यह कहा जाये कि माल उपभोग अथवा बिक्री के लिए अनुपयुक्त हो गए हैं, तब ऐसे माल पर देय शुल्क, आयुक्त अपने द्वारा लगाए शर्तों के साथ लिखित आदेश से माफ करेगा :

परन्तु जहां यह शुल्क की राशि एक हजार रुपये से अनधिक हो इस नियम के प्रावधान इस रूप में प्रभावी होंगे जैसे कि अभिव्यक्ति “समाहर्ता” के स्थान पर अभिव्यक्ति “केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक” रखा गया हो :

परन्तु जहां यह शुल्क की राशि एक हजार रुपये से अधिक हो परन्तु दो हजार पांच सौ रुपये से अनधिक हो इस नियम के प्रावधान इस रूप में प्रभावी होंगे जैसे कि अभिव्यक्ति “समाहर्ता” के स्थान पर अभिव्यक्ति “केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक समाहर्ता अथवा उपसमाहर्ता, जैसा लागू हो” रखा गया हो :—

परन्तु जहां यह शुल्क की राशि दो हजार पांच सौ रुपये से अधिक हो परन्तु पांच हजार रुपये से अनधिक हो इस नियम के प्रावधान इस रूप में प्रभावी होंगे जैसे कि अभिव्यक्ति “समाहर्ता” के स्थान पर अभिव्यक्ति “केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संयुक्त समाहर्ता अथवा अपर समाहर्ता, जैसा लागू हो” रखा गया हो :

22. **विनिर्माता के परिसरों का दौरा करने का प्राधिकार**—(1) इस निमित्त आयुक्त द्वारा सशक्त किसी अधिकारी की कोई जांच, स्थापन और निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी परिसर तक पहुंच होगी जो राजस्व के हित की सुरक्षा के लिए आवश्यक हों।

(2) हरेक निर्धारिती, उपनियम (1) के तहत सशक्त अधिकारी को, माल जिसके अंतर्गत निवेश और पूंजी माल भी हैं कि प्राप्ति, क्रय, विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या परिदान की बाबत संव्यवहारों का लेखा रखने के लिए उसके द्वारा तैयार किए गए या रखे गए सभी अभिलेखों की एक सूची दो प्रतियों में पेश करेगा।

(3) प्रत्येक निर्धारिती, उपनियम (1) के तहत सशक्त अधिकारी या आयुक्त अथवा भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा तैनात लेखा परीक्षा दल को निम्नलिखित को मांग करने पर—

(i) उपनियम (2) के तहत उसके द्वारा रखे गए या तैयार किए गए अभिलेख

(ii) कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 233 ख के अधीन लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट यदि कोई हो और

(iii) आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 44 कख के अधीन आयकर लेखा परीक्षा रिपोर्ट यदि कोई हो, यथास्थिति अधिकारी या लेखा परीक्षा दल की जांच के लिए उपलब्ध कराएगा।

23. **यानों को राकने और तलाशी लेने की शक्ति**—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून का कोई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, उत्पाद शुल्क माल को ले जा रहे किसी वाहन की तलाशी ले सकेगा जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि माल शुल्क के अपवर्चन के आशय से ले जा रहा है।

24. माल को रोकने या माल को कब्जे में लेने की शक्ति—यदि किसी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई माल ऐसा है जो उत्पाद शुल्क के लिए दायी है किन्तु उसपर कोई शुल्क संदेय नहीं किया गया है या उस को उसपर संदेय शुल्क के अपवंचन के आशय से हटाया गया था, तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी ऐसे माल को रोक सकेगा या कब्जे में ले सकेगा।

25. अधिग्रहण और शास्ति—(1) अधिनियम की धारा 11 कग के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि कोई विनिर्माता या उत्पादकर्ता, किसी भांडागार का रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी—

- (क) इन नियमों के किसी उपबंधों के उल्लंघन में किसी उत्पाद शुल्क माल को हटाता है ; या
- (ख) उसके द्वारा विनिर्मित, उत्पादित या भंडारित किसी उत्पाद शुल्क माल का लेखा नहीं रखता है ; या
- (ग) अधिनियम की धारा 6 के अधीन अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किए बिना किसी उत्पाद शुल्क माल का विनिर्माण, उत्पादन या भंडारण करता है ; या
- (घ) शुल्क के संदाय के अपवंचन के आशय से इन नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है तो सभी ऐसा माल अधिग्रहण किए जाने का दायी होगा और यथास्थिति, विनिर्माता, उत्पादनकर्ता, भांडागार का रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी उत्पाद शुल्क माल पर शुल्क से अनधिक की शास्ति जिसकी बाबत खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट प्रकृति का उल्लंघन किया है या पांच हजार रुपये इनमें से जो भी अधिक हो, का दायी होगा।

(2) उपनियम (1) के तहत कोई आदेश, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, प्राकृतिक न्याय की सिद्धांतों का पालन करते हुए जारी करेगा।

26. कतिपय अपराधों के लिए शास्ति—कोई व्यक्ति जो किसी उत्पाद शुल्क माल को कब्जे में लेता है या उसके परिवहन, हटाने, जमा करने, रखने, छुपाने, विक्रय करने या क्रय करने या किसी अन्य रीति में संव्यवहार करता है जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास विश्वास करने का यह कारण है तो वह अधिनियम या इन नियमों के अधीन अधिग्रहण का दायी होगा, ऐसे माल पर शुल्क से अनधिक की शास्ति या पांच हजार रुपये तक का इनमें से जो भी अधिक हो, का दायी होगा।

27. साधारण शास्ति—इन नियमों के अधीन कोई उल्लंघन जहां इसमें या अधिनियम में किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, शास्ति से दंडनीय होगा, जो पांच रुपए तक की हो सकेगी तथा उस माल के अधिग्रहण किए जाने के लिए दायी होगा जिसकी बाबत अपराध किया गया है।

28. अधिग्रहण पर संपत्ति का केन्द्रीय सरकार में निहित होना—(1) जब किसी चीज का इन नियमों के अधीन अधिग्रहण किया जाता है तो ऐसी वस्तु तदुपरि केन्द्रीय सरकार में निहित होगी।

(2) अधिग्रहण करने वाला अधिकारी, अधिग्रहण की गई चीजों को लेगा और अपने कब्जे में रखेगा तथा प्रत्येक पुलिस अधिकारी, ऐसे अधिकारी की अपेक्षा पर ऐसे कब्जे को लेने और रखने में उसकी सहायता करेगा।

29. अधिग्रहण किए गए माल का व्ययन—ऐसे माल का जिसका अधिग्रहण कर लिया गया है जिसकी बाबत अधिग्रहण करने के स्थान पर किसी जुर्माने के संदाय करने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया है तो उसको ऐसी रीति में विकृत, नष्ट या अन्यथा व्ययन कर दिया जाएगा जो ड्यूडिकेटिंग अधिकारी निदेश दे।

30. अधिग्रहण किए गए और मोचित किए गए माल के संबंध में भंडारण प्रभार—यदि ऐसे माल का स्वामी, जिसका अधिग्रहण कर लिया गया है, अधिग्रहण के स्थान पर जुर्माने के संदाय करने के विकल्प का प्रयोग करता है तो उससे आयुक्त द्वारा ऐसे भंडारण प्रभारों का संदाय करने की अपेक्षा की जा सकेगी जो वह उपयुक्त समझे।

31. अनुपूरक अनुदेश जारी करने की शक्ति—बोर्ड या मुख्य आयुक्त या आयुक्त, इन नियमों से उद्भूत किसी अनुपूरक विषय के लिए पबंध करने के लिए लिखित अनुदेश जारी कर सकेगा।

32. संक्रमण कालीन प्रावधान—कोई सर्कुलर, अनुदेश, स्टेंडिंग आर्डर, ट्रेड नोटिस या अन्य आदेश जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 944 के तहत बोर्ड या मुख्य आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के द्वारा जारी किए गए हैं तथा तारीख 30 जून, 2001 को प्रभावी हैं और इन नियमों के अनुरूप हैं, इन नियमों के प्रावधानों के अधीन वैध एवं जारी किए गए माने जायेंगे।

33. नियमों का विखंडन—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2001 को विखंडित किया जाता है।

[फा. सं. 354/66/2001-टीआरयू]

टी. आर. रुस्तगी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st June, 2001

No. 30/2001-CENTRAL EXCISE (N. T.)

G.S.R. 444(E).— In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and in supersession of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title, extent and commencement.— (1) These rules may be called the Central Excise (No. 2) Rules, 2001.
 - (2) They extend to the whole of India.
 - (3) They shall come into force on the 1st day of July, 2001.
2. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires, —
 - (a) “Act” means the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944);
 - (b) “assessment” includes self-assessment of duty made by the assessee and provisional assessment under rule 7;
 - (c) “assessee” means any person who is liable for payment of duty assessed or a producer or manufacturer of excisable goods or a registered person of a private warehouse in which excisable goods are stored and includes an authorized agent of such person;
 - (d) “Board” means the Central Board of Excise and Customs constituted under the Central Board of Revenue Act, 1963 (54 of 1963);
 - (e) “duty” means the duty payable under section 3 of the Act;
 - (f) “notification” means the notification published in the Official Gazette;
 - (g) “proper form” means the appropriate form as may be notified by the Board;
 - (h) “warehouse” means any place or premises registered under rule 9; and
 - (i) words and expressions used herein but not defined and defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
3. Appointment and jurisdiction of Central Excise Officers.— (1) The Board may, by notification, appoint such person as it thinks fit to be Central Excise Officer or to exercise all or any of the powers conferred by these rules, on such officer.
 - (2) The Board may, by notification, specify the jurisdiction of a Chief Commissioner of Central Excise, Commissioner of Central Excise or Commissioner of Central Excise (Appeals) for the purposes of the Act and the rules made thereunder.
 - (3) Any Central Excise Officer may exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed under the Act or these rules on any other Central Excise Officer who is subordinate to him.
4. Duty payable on removal.— (1) Every person who produces or manufactures any excisable goods, or who stores such goods in a warehouse, shall pay the duty leviable on such goods in the manner provided in rule 8 or under any other law, and no excisable goods, on which any duty is payable, shall be

removed without payment of duty from any place, where they are produced or manufactured, or from a warehouse, unless otherwise provided:

Provided that the goods falling under Chapter 62 of the First Schedule to Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) produced or manufactured by a job worker may be removed without payment of duty leviable thereon and the duty of excise leviable on such goods shall be paid by the person referred to in sub-rule (3), as if such goods have been produced or manufactured by him, on the date of removal of such goods from his premises registered under rule 9:

Explanation.- It is hereby clarified that where such person has authorised the job worker to pay the duty leviable on such goods under sub-rule (3), such duty shall be paid by the job worker on the date of removal of such goods from his registered premises.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), where molasses are produced in a khandsari sugar factory, the person who procures such molasses, whether directly from such factory or otherwise, for use in the manufacture of any commodity, whether or not excisable, shall pay the duty leviable on such molasses, in the same manner as if such molasses have been produced by the procurer.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), every person who gets the goods, falling under Chapter 62 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), produced or manufactured on his account on job work, shall pay the duty leviable on such goods, at such time and in such manner as may be specified under these rules, whether the payment of such duty be secured by bond or otherwise, as if such goods have been manufactured by such person:

Provided that such person may authorise the job worker to pay the duty leviable on such goods on his behalf and the job worker so authorised undertakes to discharge all liabilities and comply with all the provisions of these rules.

Explanation I.- For the purposes of this sub-rule, the expression "job worker" shall be deemed to mean the person who undertakes the process or processes that brings into existence the finished goods, complete in all respects, falling under Chapter 62 of the said First Schedule, in his factory. For the removal of doubt, it is further clarified that the job-worker may also get part of the processing required for the manufacture of the said goods done by another person but should bring back the same for the completion of the manufacturing process in his factory.

Explanation II.- For the purposes of this rule, excisable goods manufactured in a factory and utilised, as such or after subjecting to any process, for the manufacture of any other commodity, in such factory shall be deemed to have been removed from such factory immediately before such utilisation.

5. Date for determination of duty and tariff valuation.- (1) The rate of duty or tariff value applicable to any excisable goods, other than khandsari molasses, shall be the rate or value in force on the date when such goods are removed from a factory or a warehouse, as the case may be.

(2) The rate of duty in the case of khandsari molasses, shall be the rate in force on the date of receipt of such molasses in the factory of the procurer of such molasses.

Explanation.- If any excisable goods are used within the factory, 'the date of removal of such goods' shall mean the date on which the goods are issued for such use.

(3) The rate of duty in the case of goods falling under Chapter 62 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), produced or manufactured on job work, shall be the rate in force on the date of removal of such goods by the person referred to in sub-rule (3) of rule 4 from his premises registered under rule 9.

6. Assessment of duty.- The assessee shall himself assess the duty payable on any excisable goods:

Provided that in case of cigarettes, the Superintendent or Inspector of Central Excise shall assess the duty payable before removal by the assessee.

7. Provisional assessment.- (1) Where the assessee is unable to determine the value of excisable goods or determine the rate of duty applicable thereto, he may request the Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, in writing giving reasons for payment of duty on provisional basis and the Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, may order allowing payment of duty on provisional basis at such rate or on such value as may be specified by him.

(2) The payment of duty on provisional basis may be allowed, if the assessee executes a bond in proper form with such surety or security in such amount as the Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, deem fit, binding the assessee for payment of difference between the amount of duty as may be finally assessed and the amount of duty provisionally assessed.

(3) The Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, shall pass order for final assessment, as soon as may be, after the relevant information, as may be required for finalizing the assessment, is available, but within a period not exceeding six months from the date of the communication of the order issued under sub-rule (1):

Provided that the period specified in this sub-rule may, on sufficient cause being shown and the reasons to be recorded in writing, be extended by the Commissioner of Central Excise for a further period not exceeding six months and by the Chief Commissioner of Central Excise for such further period as he may deem fit.

(4) The assessee shall be liable to pay interest on any amount payable to Central Government, consequent to order for final assessment under sub-rule (3), at the rate of twenty four percent per annum from the first day of the month succeeding the month for which such amount is determined, till the date of payment thereof.

(5) Where the assessee is entitled to a refund consequent to order for final assessment under sub-rule (3), subject to sub-rule (6), there shall be paid an interest on such refund at the rate of fifteen percent per annum from the first day of the month succeeding the month for which such refund is determined, till the date of refund.

(6) Any amount of refund determined under sub-rule (3) shall be credited to the Consumer Welfare Fund:

Provided the amount of refund, instead of being credited to the Fund, be paid to the applicant, if such amount is relatable to-

- (a) the duty of excise paid by the manufacturer, if he had not passed on the incidence of such duty to any other person, or
- (b) the duty of excise borne by the buyer, if he had not passed on the incidence of such duty to any other person.

8. Manner of payment.- (1) The duty on the goods removed from the factory or the warehouse during the first fortnight of the month shall be paid by the 20th of that month and the duty on the goods removed from the factory or the warehouse during the second fortnight of the month shall be paid by the 5th of the following month:

Provided that in the case of goods removed during the second fortnight of the month of March, the duty shall be paid by 31st day of March:

Provided further that where an assessee is availing of the exemption under a notification based on the value of clearances in a financial year, the duty on goods cleared during a calendar month shall be paid by the 15th day of the following month.

Explanation.- For removal of doubts, it is hereby clarified that the duty liability shall be deemed to have been discharged only if the amount payable is credited to the account of the Central Government by the specified date.

(2) The duty of excise shall be deemed to have been paid for the purpose of these rules on the excisable goods removed in the manner provided under sub-rule (1) and the credit of such duty allowed, as provided by or under any rule.

(3) If the assessee fails to pay the amount of duty by due date, he shall be liable to pay the outstanding amount alongwith interest at the rate of twenty four per cent. per annum on the outstanding amount, for the period starting with the first day after due date till the date of actual payment of the outstanding amount.

(4) If the assessee defaults,-

(i) in payment of any one instalment and the same is discharged beyond a period of thirty days from the date on which the instalment was due in a financial year, or

(ii) in payment of instalment by the due date for the third time in a financial year, whether in succession or otherwise,

then, the assessee shall forfeit the facility to pay the dues in instalments under this rule for a period of two months, starting from the date of communication of the order passed by the Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, in this regard or till such date on which all dues are paid, whichever is later, and during this period the assessee shall be required to pay excise duty for each consignment by debit to the account current and in the event of any failure, it shall be deemed that such goods have been cleared without payment of duty and the consequences and penalties as provided in these rules shall follow.

9. Registration.- (1) Every person, who produces, manufactures, carries on trade, holds private store-room or warehouse or otherwise uses excisable goods, shall get registered:

Provided that a registration obtained under rule 174 of the Central Excise Rules, 1944 shall be deemed to be as valid as the registration made under this sub-rule for the purpose of these rules.

(2) The Board, may, by notification, and subject to such conditions or limitations as may be specified in such notification, specify person or class of persons who may not require such registration.

(3) The registration under sub-rule (1) shall be subject to such conditions, safeguards and procedure as may be notified by the Board.

10. Daily stock account.- (1) Every assessee shall maintain proper records, on a daily basis, in a legible manner indicating the particulars regarding description of the goods produced or manufactured, opening balance, quantity produced or manufactured, inventory of goods, quantity removed, assessable value, the amount of duty payable and particulars regarding amount of duty actually paid.

(2) The first page and the last page of each such account book shall be duly authenticated by the producer or the manufacturer or his authorised agent.

(3) All such records shall be preserved for a period of five years immediately after the financial year to which such records pertain.

11. Goods to be removed on invoice.- (1) No excisable goods shall be removed from a factory or a warehouse except under an invoice signed by the owner of the factory or his authorized agent and in the case of cigarettes, each such invoice shall also be countersigned by the Inspector of Central Excise or the Superintendent of Central Excise before the cigarettes are removed from the factory.

(2) The invoice shall be serially numbered and shall contain the registration number, description, classification, time and date of removal, rate of duty, quantity and value, of goods and the duty payable thereon.

(3) The invoice shall be prepared in triplicate in the following manner, namely:-

- (i) the original copy being marked as ORIGINAL FOR BUYER;
- (ii) the duplicate copy being marked as DUPLICATE FOR TRANSPORTER;
- (iii) the triplicate copy being marked as TRIPLICATE FOR ASSESSEE.

(4) Only one copy of invoice book shall be in use at a time, unless otherwise allowed by the Assistant Commissioner of Central Excise, or the Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, in the special facts and circumstances of each case.

(5) The owner or working partner or Managing Director or Company Secretary shall authenticate each foil of the invoice book, before being brought into use.

(6) Before making use of the invoice book, the serial numbers of the same shall be intimated to the Superintendent of Central Excise having jurisdiction.

12. Filing of return.- Every assessee shall submit to the Superintendent of Central Excise a monthly return in proper form, of production and removal of goods and other relevant particulars, within ten days after the close of the month to which the return relates:

Provided that where an assessee is availing of the exemption under a notification based on the value of clearances in a financial year, he shall file a quarterly return in proper form, of production and removal of goods and other relevant particulars, within twenty days after the close of the quarter to which the return relates.

13. Duty on matches.- The duty on matches shall be paid by affixing to each box or booklet a Government Central Excise Stamp of a value appropriate to the rate of duty, and where such boxes or booklets are issued in packages, each package shall be reckoned by the manufacturer as his minimum unit of distribution and shall bear the manufacturer's trade label and a mark clearly showing the class of matches contained in the package.

14. Procedure for procurement of central excise stamps and maintenance of records for production and removal of matches.- The Board may, by notification, specify the procedure for procurement, accounting and disposal of Central Excise Stamps and matters pertaining to production, storage, control, removal and payment of duty on matches.

15. Special procedure for payment of duty.- (1) . The Central Government may, by notification, specify the goods in respect of which an assessee shall have the option to pay the duty of excise on the basis of such factors as may be relevant to production of such goods and at such rate as may be notified for this purpose.

(2) The Central Government may also specify by notification the manner of making an application for availing of the special procedure for payment of duty, the abatement, if any, that may be allowed on account of closure of a factory during any period, and any other matter incidental thereto.

16. Credit of duty on goods returned to the factory.- (1) Where any goods on which duty has been paid at the time of removal thereof are subsequently returned to the factory for being re-made, refined, re-conditioned or for any other reason, the assessee shall state the particulars of such return in his records and shall be entitled to have CENVAT credit of the duty paid as if such goods are received as inputs under the CENVAT Credit Rules, 2001 and utilise this credit according to the said rules.

(2) If the process to which the goods are subjected before returning does not amount to manufacture, the manufacturer shall pay an amount equal to the CENVAT credit taken under sub-rule (1) and in any other case the manufacturer shall pay duty on goods returned under sub-rule (1) at the rate applicable on the date of removal and on the value determined under section 4 or section 4A of the Act, as the case may be.

(3) If there is any difficulty in following the provisions of sub-rule (1) and sub-rule (2), the assessee may receive the goods for being re-made, refined, re-conditioned or for any other reason and may remove the goods subsequently subject to such conditions as may be specified by the Commissioner.

17. Removal of goods by a unit in the Free Trade Zone or by a Hundred per cent. Export-Oriented undertaking or by a unit in the Special Economic Zone for Domestic Tariff Area.- (1) Where any goods are removed from a unit in a Free Trade Zone or a hundred per cent. export-oriented unit or a unit in the Special Economic Zone, to domestic tariff area, such removal shall be made under an invoice by following the procedure specified in rule 11, and on payment of appropriate duty before removal of goods by debiting the account current required to be maintained for this purpose.

(2) The unit shall maintain in proper form appropriate account relating to production, description of goods, quantity removed, duty paid and each removal shall be made on an invoice.

(3) The unit shall submit a monthly return to the Superintendent of Central Excise, within ten days from the close of the month to which the return relates, in respect of the goods removed to domestic tariff area in such form as may be notified by the Board for this purpose.

18. Rebate of duty.- Where any goods are exported, the Central Government may, by notification, grant rebate of duty paid on such excisable goods or duty paid on materials used in the manufacture or processing of such goods and the rebate shall be subject to such conditions or limitations, if any, and fulfillment of such procedure, as may be specified in the notification.

Explanation.- "Export" includes goods shipped as provision or stores for use on board a ship proceeding to a foreign port or supplied to a foreign going aircraft.

19. Export without payment of duty.- (1) Any excisable goods may be exported without payment of duty from a factory of the producer or the manufacturer or the warehouse or any other premises, as may be approved by the Commissioner.

(2) Any material may be removed without payment of duty from a factory of the producer or the manufacturer or the warehouse or any other premises, for use in the manufacture or processing of goods which are exported, as may be approved by the Commissioner.

(3) The export under sub-rule (1) or sub-rule (2) shall be subject to such conditions, safeguards and procedure as may be notified by the Board.

20. Warehousing provisions.- (1) The Central Government may by notification, extend the facility of removal of any excisable goods from the factory of production to a warehouse, or from one warehouse to another warehouse without payment of duty.

(2) The facility under sub-rule (1) shall be available subject to such conditions (including penalty and interest), limitations (including limitation with respect to the period for which the goods may remain in the warehouse) and safeguards and procedure (including in the matters relating to dispatch, movement, receipt, accountal and disposal of such goods) as may be specified by the Board in this behalf.

(3) The responsibility for payment of duty on the goods that are removed from the factory of production to a warehouse or from one warehouse to another warehouse shall be upon the consignee.

(4) If the goods dispatched for warehousing or re-warehousing are not received in the warehouse, the responsibility for payment of duty shall be upon the consignor.

21. Remission of duty.- Where it is shown to the satisfaction of the Commissioner that goods have been lost or destroyed by natural causes or by unavoidable accident or are claimed by the manufacturer as unfit for consumption or for marketing, at any time before removal, he may remit the duty payable on such goods, subject to such conditions as may be imposed by him by order in writing:

Provided that where such duty does not exceed one thousand rupees, the provisions of this rule shall have effect as if for the expression "Commissioner", the expression "Superintendent of Central Excise" has been substituted:

Provided further that where such duty exceeds one thousand rupees but does not exceed two thousand five hundred rupees, the provisions of this rule shall have effect as if for the expression "Commissioner", the expression "Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be," has been substituted:

Provided further that where such duty exceeds two thousand five hundred rupees but does not exceed five thousand rupees, the provisions of this rule shall have effect as if for the expression "Commissioner", the expression "Joint Commissioner of Central Excise or Additional Commissioner of Central Excise, as the case may be," has been substituted.

22. Access to a registered premises.- (1) An officer empowered by the Commissioner in this behalf shall have access to any premises registered under these rules for the purpose of carrying out any scrutiny, verification and checks as may be necessary to safeguard the interest of revenue.

(2) Every assessee shall furnish to the officer empowered under sub-rule (1), a list in duplicate, of all the records prepared or maintained by the assessee for accounting of transactions in regard to receipt, purchase, manufacture, storage, sales or delivery of the goods including inputs and capital goods.

(3) Every assessee shall, on demand make available to the officer empowered under sub-rule (1) or the audit party deputed by the Commissioner or the Comptroller and Auditor General of India,-

- (i) the records maintained or prepared by him in terms of sub-rule (2);
- (ii) the cost audit reports, if any, under section 233B of the Companies Act, 1956 (1 of 1956); and
- (iii) the Income-tax audit report, if any, under section 44AB of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),

for the scrutiny of the officer or audit party, as the case may be.

23. Power to stop and search .- Any Central Excise Officer, may search any conveyance carrying excisable goods in respect of which he has reason to believe that the goods are being carried with the intention of evading duty.

24. Power to detain goods or seize the goods.- If a Central Excise Officer, has reason to believe that any goods, which are liable to excise duty but no duty has been paid thereon or the said goods were removed with the intention of evading the duty payable thereon, the Central Excise Officer may detain or seize such goods.

25. Confiscation and penalty.- (1) Subject to the provisions of section 11 AC of the Act, if any producer, manufacturer, registered person of a warehouse or a registered dealer, —

- (a) removes any excisable goods in contravention of any of the provisions of these rules or the notifications issued under these rules; or
- (b) does not account for any excisable goods produced or manufactured or stored by him; or
- (c) engages in the manufacture, production or storage of any excisable goods without having applied for the registration certificate required under section 6 of the Act; or

(d) contravenes any of the provisions of these rules or the notifications issued under these rules with intent to evade payment of duty,-

then, all such goods shall be liable to confiscation and the producer or manufacturer or registered person of the warehouse or a registered dealer, as the case may be, shall be liable to a penalty not exceeding the duty on the excisable goods in respect of which any contravention of the nature referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) has been committed, or rupees ten thousand, whichever is greater.

(2) An order under sub-rule (1) shall be issued by the Central Excise Officer, following the principles of natural justice.

26. Penalty for certain offences.- Any person who acquires possession of, or is in any way concerned in transporting, removing, depositing, keeping, concealing, selling or purchasing, or in any other manner deals with, any excisable goods which he knows or has reason to believe are liable to confiscation under the Act or these rules, shall be liable to a penalty not exceeding the duty on such goods or rupees ten thousand, whichever is greater.

27. General penalty.- A breach of these rules shall, where no other penalty is provided herein or in the Act, be punishable with a penalty which may extend to five thousand rupees and with confiscation of the goods in respect of which the offence is committed.

28. On confiscation, property to vest in the Central Government.- (1) When any goods are confiscated under these rules, such thing shall thereupon vest in the Central Government.

(2) The Central Excise Officer adjudging confiscation shall take and hold possession of the things confiscated, and every Officer of Police, on the requisition of such Central Excise Officer, shall assist him in taking and holding such possession.

29. Disposal of goods confiscated.- Goods of which confiscation has been adjudged and in respect of which the option of paying a fine in lieu of confiscation has not been exercised, shall be sold, destroyed or otherwise disposed of in such manner as the Commissioner may direct.

30. Storage charges in respect of goods confiscated and redeemed.- If the owner of the goods, the confiscation of which has been adjudged, exercises his option to pay fine in lieu of confiscation, he may be required to pay such storage charges as may be determined by the adjudicating officer.

31. Power to issue supplementary instructions.- (1) The Board or the Chief Commissioner or the Commissioner, may issue written instructions providing for any incidental or supplemental matters, consistent with the provisions of the Act and these rules.

32. Transitional provisions.- Any circulars, instructions, standing orders, trade notices or other orders issued under the Central Excise Rules, 1944 by the Board, the Chief Commissioner or the Commissioner of Central Excise, and in force as on 30th June, 2001, shall, to the extent they are relevant and consistent with these rules, be deemed to be valid and issued under the corresponding provisions of these rules.

33. Rescinding of rules.- The Central Excise Rules, 2001 is hereby rescinded.

[F. No. 354/66/2001-TRU]
T. R. RUSTAGI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2001

सं० 31/2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.)

सा. का. नि. 445(अ).—केन्द्रीय सरकार, उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, का निम्न संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) ये नियम सेनबेट प्रत्यय नियम, 2001 कहे जाएंगे।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) ये 1 जुलाई, 2001 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि उक्त विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो—

(क) “अधिनियम” से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) अभिप्रेत है;

(ख) “पूँजी माल” से अंतिम उत्पादों के विनिर्माता के कारखाने में प्रयुक्त—

(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची (जिसे इसमें इसके पश्चात् पहली अनुसूची कहा गया है) के अध्याय 82, अध्याय 84, अध्याय 85, अध्याय 90, शीर्ष सं० 68.02 और उपशीर्ष सं० 6801.10 के अंतर्गत आने वाले सभी माल;

(ii) ऊपर (i) में विनिर्दिष्ट मालों के संबटक, फालतू पुर्जे और उपसाधन;

(iii) सांघे और झाइयां;

(iv) उच्चताप सह और उच्चताप सह सामग्री;

(v) ट्यूब और पाइप तथा उनकी फिटिंग;

(vi) प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर, और

(vii) भंडारकरण टैंक।

अभिप्रेत हैं, परन्तु इसके अंतर्गत किसी कार्यालय में प्रयुक्त उपस्कर या माधित्र नहीं आते हैं;

(ग) “छूट प्राप्त मालों” से ऐसे माल अभिप्रेत हैं जो उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त हैं और इसके अंतर्गत ऐसे माल भी हैं जो शुल्क की “शून्य” दर से प्रभाव्य हैं;

(घ) “अंतिम उत्पाद” से दियासलाई को छोड़ कर निवेशों से विनिर्मित या उत्पादित उत्पाद शुल्क्य माल अभिप्रेत हैं;

(ङ) “प्रथम प्रक्रम व्यौहारी” से ऐसा व्यौहारी अभिप्रेत है जो माल सीधे निम्नलिखित से क्रय करता है :—

(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सं० 2) नियम 2001 के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार जारी किए गए किसी बीजक के अधीन विनिर्माता से या उक्त विनिर्माता के डिपो से या उक्त विनिर्माता के परेपण अभिकर्ता के परिसरों से या किसी अन्य परिसर से, जहां से माल उक्त विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से किसी बीजक के अधीन विक्रय किया जाता है; या

(ii) किसी आयातकर्ता से या किसी आयातकर्ता के डिपो से या आयातकर्ता के परेपण अभिकर्ता के परिसरों से बीजक के अधीन सीधे माल क्रय करता है;

(च) “निवेश” से डब्लुवेग तेल और मोटर स्मिरिट जो सामान्य रूप से पेट्रोल के नाम से जाना जाता है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में या उसके संबंध में उपयोग किया जाता है और चाहे अंतिम उत्पाद में अंतर्निष्ठ हो या न हो और इसके अंतर्गत अंतिम उत्पादों के साथ निकासी किए गए स्नेहक तेल, ग्रीज, कर्तन तेल शीतक, अंतिम उत्पादों के उपसाधन, पेंट के रूप में, या पैकिंग सामग्री के रूप में या ईंधन के रूप में, उत्पादन के कारखाने के भीतर अंतिम उत्पादों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त विद्युत या भाप के उत्पादन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त माल अभिप्रेत हैं।

स्पष्टीकरण I :—उच्च वेग डीजल या मोटर स्मिरिट जो सामान्यता पेट्रोल के नाम से जाना जाता है कभी भी किसी प्रयोजन के लिए निवेश के रूप में नहीं माना जाएगा।

स्पष्टीकरण II :—निवेश के अंतर्गत पूंजी माल के विनिर्माण में प्रयुक्त माल सम्मिलित है जो विनिर्माता के कारखाने में प्रयुक्त किये जाते हैं;

(छ) उक्त पहली अनुसूची के अध्याय 62 के अधीन आने वाले माल की बाबत “विनिर्माता” या “उत्पादक” के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति सम्मिलित होगा जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सं० 2) नियम 2001 के नियम 4 के अधीन ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क का संदाय करने का दायी है;

- (ज) "टैरिफ अधिनियम" से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) अभिप्रेत है;
- (झ) "द्वितीय प्रक्रम व्यौहारी" से ऐसा व्यौहारी अभिप्रेत है जो प्रथम प्रक्रम व्यौहारी से माल क्रय करता है;
- (अ) उन शब्दों और पदों का जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु जो अधिनियम में परिभाषित हैं क्रमशः वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है।

3. सैनवेट प्रत्यय—(1) अंतिम उत्पादों के विनिर्माता या उत्पादक निम्नलिखित का प्रत्यय (जिसे इसमें इसके पश्चात् सैनवेट प्रत्यय कहा गया है) लेने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा—

- (i) उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क जो अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय है;
- (ii) टैरिफ अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क जो अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय है;
- (iii) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क;
- (iv) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क;
- (v) वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क; और
- (vi) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क जो उपरोक्त खंड (i), (ii), (iii), (iv) और (v) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क के समतुल्य है, जिसे 1 जुलाई, 2001 को या उसके पश्चात् कारखाने में प्राप्त किसी निवेश या पूंजी माल जिसके अंतर्गत भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 214/86-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 25 मार्च, 1986 जो भारत के राजपत्र में सा०का०नि० सं० 547(अ) तारीख 25 मार्च, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में विनिर्दिष्ट छूट के फायदा लेने वाले फुटकर कर्मकार द्वारा मध्यवर्ती उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त किसी निवेश संदत्त शुल्क भी है और 1 जुलाई, 2001 या इसके पश्चात् अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग के लिए या इसके संबंध में विनिर्माता द्वारा प्राप्त किसी निवेश या पूंजी माल पर संदत्त किया गया है।

स्पष्टीकरण :—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि अंतिम उत्पादों के विनिर्माता को उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, की पहली अनुसूची के शीर्ष सं० 98.01 के अधीन आने वाले माल पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क का सैनवेट प्रत्यय अनुज्ञात किया जाएगा।

(2) उप नियम (1) में किसी बात के होते हुए, अंतिम उत्पादों के विनिर्माता या उत्पादक को उस तारीख को जिसको कोई माल छूट प्राप्त नहीं रह जाता है या कोई माल उत्पाद शुल्क बन जाता है, स्टॉक में पड़े हुए उत्पादों या प्रक्रिया में निवेश पर या स्टॉक में पड़े हुए अंतिम उत्पादों में अंतर्विष्ट निवेश पर सैनवेट प्रत्यय लेने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(3) सैनवेट प्रत्यय किसी अंतिम उत्पाद का उत्पाद शुल्क के संदाय के लिए या निवेश या पूंजी माल पर शुल्क के संदाय के लिए उपयोग किया जाएगा, यदि ऐसा निवेश उसी रूप में हटायें जाते हैं या आंशिक रूप से प्रसंस्कृत किये जाने के पश्चात् या ऐसे पूंजी माल उसी रूप में हटायें जाते हैं।

परन्तु शुल्क का संदाय करते समय सैनवेट प्रत्यय केवल उस विस्तार तक उपयोग किया जाएगा जिस तक ऐसा प्रत्यय मास के पहले पखवाड़े से संबंधित शुल्क के संदाय के लिए मास के पन्द्रह दिनों को और मास के दूसरे पखवाड़े से संबंधित शुल्क के संदाय के लिए किसी मास के अंतिम दिन या सम्पूर्ण मास से संबंधित शुल्क के संदाय के लिए किसी वित्तीय वर्ष में निकासी के मूल्य पर आधारित अधिसूचना द्वारा छूट का फायदा उठाने वाले विनिर्माता की दशा में उपलब्ध है।

(4) जब निवेश या पूंजी माल, जिस पर सैनवेट प्रत्यय लिया गया है, कारखाने से इस प्रकार हटाई जाती है कि तब अंतिम उत्पादों का विनिर्माता उस उत्पाद शुल्क के बराबर रकम का संदाय करेगा जो ऐसे हटाए जाने की तारीख को ऐसे माल को लागू सदर पर ऐसे माल पर और अधिनियम की धारा 4 के अधीन ऐसे माल के लिए अवधारित मूल्य पर उद्ग्रहणीय है और ऐसा हटाया जाना नियम 7 में निर्दिष्ट किसी बीजक के अंतर्गत किया जाएगा।

(5) उप नियम (4) के अधीन संदत्त रकम सैनवेट प्रत्यय के रूप में उसी प्रकार पात्र होगी मानो यह उपनियम (4) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा जो ऐसे माल को हटाता, संदत्त शुल्क हो।

(6) उप नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए—

(क) निम्नलिखित में उत्पादित या विनिर्मित निवेश या पूंजी माल की बाबत सैनवेट प्रत्यय,—

- (i) मुक्त व्यापार जोन या किसी विशेष आर्थिक जोन में और जो भारत में किसी अन्य स्थान पर अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त किया गया है; या
- (ii) किसी शत-प्रतिशत निर्यातानुमुख उपक्रम द्वारा या किसी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क में या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में किसी यूनिट द्वारा और जो भारत में किसी स्थान पर अंतिम उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त किया गया है;

उस विस्तार तक निर्बंधित होगा जिस तक वह ऐसे निदेश या पूंजी माल पर संदत्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन वैसे ही माल पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क के समान है।

(ख) निम्नलिखित की बाबत सेनवेट प्रत्यय—

- (i) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ;
- (ii) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 88) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ;
- (iii) वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 के अधीन राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क ; और
- (iv) उपरोक्त खंड (i), (ii) और (iii) के अधीन विभिन्न उत्पाद शुल्क के समेतुल्य सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन अतिरिक्त शुल्क क्रमशः उक्त अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) अधिनियम के अधीन या उक्त अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, या वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 के अधीन राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क, विनिर्माता द्वारा विनिर्मित किसी अंतिम उत्पाद पर या उस निवेश पर, यदि ऐसा निवेश इस रूप में हटा लिया जाता है या आंशिक रूप से प्रसंस्कृत करने के पश्चात् ऐसे शुल्क के संदाय के लिए उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के संदाय के लिए ही उपयोग किया जाएगा।

(ग) उक्त प्रथम अनुसूची के क्रमशः उपशीर्ष सं. 2504-21 या 2504.31 के अंतर्गत आने वाले मार्बल स्लैब या टाइलों पर संदत्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क की बाबत सेनवेट प्रत्यय तीस रुपये प्रति वर्ग मीटर की सीमा तक अनुज्ञात किया जाएगा ;

(घ) निवेशों पर संदत्त शुल्क का सेनवेट प्रत्यय टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्ष सं. 54.02 के अंतर्गत आने वाले पालिस्ट्रो के संव्यूतित सूत (जिनके कर्षण—व्यावृत्त या कर्षण लपेटा हुआ सूत भी है) जो एक स्वतंत्र संव्यूतितक द्वारा विनिर्मित है अर्थात् शीर्ष सं. 54.02 के अंतर्गत आने वाले पालिस्ट्र के संव्यूतित सूत (जिसमें कर्षण व्यावृत्त या कर्षण लपेटा हुआ सूत भी है) जो टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के उपशीर्ष सं. 54.02 के अंतर्गत आने वाले पालिस्ट्रो के आंशिकतः अभिसंस्कृत सूत के ऐसे विनिर्माता के लिए जिसके अपने कारखाने में (जिसमें संयंत्र और मशीनरी भी है) सुविधा नहीं है, की बाबत अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :—जहां किसी अन्य नियम या अधिसूचना के उपबंध किसी निवेश या पूंजी माल पर संदत्त शुल्क के प्रत्यय की अनुपलब्धता की शर्त पर आंशिक या पूर्ण छूट देने के लिए उपबंध करते हैं वहां, ऐसे अन्य नियम या अधिसूचना के उपबंध इन नियमों के उपबंधों के अभिभावी होंगे।

4. सेनवेट प्रत्यय को अनुज्ञात करने के लिए शर्तें—(1) निवेशों की बाबत सेनवेट प्रत्यय विनिर्माता के कारखाने में निवेशों की प्राप्ति पर तुरंत लिया जा सकेगा :

परंतु टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय 62 के अंतर्गत आने वाले अंतिम उत्पादों की बाबत, निवेशों पर संदत्त शुल्क का सेनवेट प्रत्यय, ऐसे व्यक्ति के, जो छुट-पुट कार्य में अपने लेखा में विनिर्मित ऐसे अंतिम उत्पाद इस शर्त के अधीन रहते हुए प्राप्त करता है कि ऐसे निवेश छुट-पुट कर्मकार द्वारा ऐसे अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं, रजिस्ट्रीकृत परिसरों में ऐसे निवेशों की प्राप्ति पर तुरंत लिया जा सकेगा।

(2) (क) किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में किसी समय पर किसी कारखाने में प्राप्त पूंजीमाल की बाबत सेनवेट प्रत्यय उसी वित्तीय वर्ष में ऐसे पूंजी माल पर संदत्त शुल्क के पचास प्रतिशत से अधिक की रकम के लिए ही लिया जा सकेगा।

(ख) सेनवेट प्रत्यय का अतिशेष ऐसे वित्तीय वर्ष के पश्चात् किसी वित्तीय वर्ष में लिया जा सकेगा जिसमें पूंजी माल विनिर्माता के कारखाने में प्राप्त किए गए थे परंतु यह तब जब कि उक्त पहली अनुसूची के शीर्ष सं. 8602 और उपशीर्ष सं. 6801.10 के अंतर्गत आने वाले संघटकों, पुंजों और साधित्रों, उच्च ताप सह और उच्च ताप सह सामग्री और माल से भिन्न पूंजी माल ऐसे पश्चात्कर्तव्य वर्षों से अंतिम उत्पादों के विनिर्माता के कब्जे में हो और उपयोग में है।

दृष्टांत—किसी विनिर्माता ने 16 अप्रैल, 2001 को अपने कारखाने में मशीनरी प्राप्त की। दो लाख रु. का सेनवेट इस मशीनरी पर संदाय किया जाता है। विनिर्माता वित्तीय वर्ष 2001-2002 में अधिकतम एक लाख रु. का प्रत्यय और अतिशेष पश्चात्कर्तव्य वर्षों में ले सकेगा।

(3) पूंजी माल की बाबत सेनवेट प्रत्यय किसी विनिर्माता को अनुज्ञात किया जायेगा भले ही वह पूंजी माल को किसी वित्त पोषण कंपनी से पट्टे; क्रय या उधार करार पर अर्जित करे।

(4) पूंजीमाल की बाबत सेनवेट प्रत्यय पूंजी माल के मूल के उस भाग की बाबत अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जो ऐसे पूंजी माल पर शुल्क की रकम का वर्णन करता है जिसे विनिर्माता आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 32 के अधीन अवक्षयण के रूप में दावा करता है।

(5) (क) सेनवेट प्रत्यय तब भी अनुज्ञात किया जायेगा जब कोई निवेश या पूंजी माल उस रूप में या आंशिक रूप से प्रसंस्कृत किए जाने के पश्चात् किसी छूट-पुट कर्मकार के पास और प्रसंस्करण, परीक्षण, मरम्मत, पुनः ठीक किए जाने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए भेजा जाता है और सेनवेट प्रत्यय लेने के लिए किसी निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेख, चालान या ज्ञापन या किसी अन्य दस्तावेज से यह साबित हो जाता है कि माल किसी छूट-पुट कर्मकार को भेजे जाने की तारीख से 180 दिन के भीतर कारखाने में पुनः प्राप्त हो गए हैं और यदि निवेश या पूंजी माल 180 दिन के भीतर पुनः प्राप्त नहीं होता तो विनिर्माता सेनवेट प्रत्यय नामे करके या अन्य निवेश या पूंजी माल पर सेनवेट प्रत्यय के समतुल्य रकम का संदाय करेगा। किंतु विनिर्माता, जब निवेश या पूंजी माल उसके कारखाने में वापस आ जाता है तो पुनः सेनवेट प्रत्यय ले सकेगा।

(ख) सेनवेट प्रत्यय ऐसे जियों, फिक्सवर्कों, सांघों और डाइयों की बाबत भी अनुज्ञात किया जाएगा जो अंतिम उत्पादों के विनिर्माता द्वारा किसी छूट-पुट कर्मकार को, उसके भित्त और उसके विनिर्देशों के अनुसार माल के उत्पादन के लिए भेजी जाती है।

(6) अंतिम उत्पादों के विनिर्माता के, जिसने अपने कारखाने से बाहर निवेश या भागतः प्रसंस्कृत निवेश किसी छूट-पुट कर्मकार को भेजे हैं, कारखाने पर अधिकारिता रखने वाला केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, ऐसे निवेश या भागतः प्रसंस्कृत निवेश के हटाए जाने की बाबत और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह राजस्व के हित में अधिरोपित करे जिसके अंतर्गत वह रीति भी है जिसमें शुल्क, यदि उद्ग्रहणीय है, तो संदत्त किया जाना है, आदेश द्वारा जो एक वित्तीय वर्ष के लिए विधि मान्य रहेगा, छूट-पुट कर्मकार के परिसर से अंतिम उत्पाद की निकासी अनुज्ञात कर सकेगा।

5. सेनवेट प्रत्यय का प्रतिदाय—(1) जहां किसी निवेशों का ऐसे अंतिम उत्पाद में प्रयोग किया जाता है, जो बंधपत्र के अधीन निर्यात के लिए निकाले जाते हैं या निर्यात के लिए निकाले गए मध्यवर्ती उत्पादों में प्रयुक्त होते वहां इस प्रकार प्रयुक्त निवेशों की बाबत सेनवेट प्रत्यय का विनिर्माता द्वारा घरेलू उपभोग के लिए निकाले गए किसी अंतिम उत्पाद पर उत्पाद शुल्क के संदाय मुद्दे या शुल्क के संदाय पर निर्यात के लिए उपभोग किए जाने की अनुज्ञा दी जाएगी और जहां किसी कारण से ऐसा समायोजन संभव नहीं है वहां निर्माता के ऐसे रक्षोपायों, शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकेगी, ऐसे रकम का प्रतिदाय अनुज्ञात किया जाएगा।

परंतु यह कि प्रत्यय का प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा यदि विनिर्माता सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम, 1995 के अधीन अनुज्ञात शुल्क वापसी का उपभोग करता है या ऐसे शुल्क की बाबत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2001 के अधीन शुल्क के रिबेट का दावा करता है।

6. शुल्क योग्य और छूट प्राप्त माल के विनिर्माता की बाध्यता—(1) सेनवेट प्रत्यय, निवेशों की ऐसी मात्रा पर अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जो, उपनियम (2) में उल्लिखित परिस्थितियों में के सिवाय, छूट प्राप्त माल के विनिर्माण में होती है।

(2) जहां कोई विनिर्माता, ईंधन के रूप में प्रयोग के लिए आशयित निवेशों के सिवाय किसी निवेश की बाबत सेनवेट प्रत्यय का उपयोग करता है और ऐसे अंतिम उत्पादों का विनिर्माण करता है, जो शुल्क से प्रभार्य है, और साथ ही छूट प्राप्त माल है, जहां विनिर्माता शुल्क योग्य अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित निवेशों की प्राप्ति उपयोग और माल सूची के लिए छूट प्राप्त माल के विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित निवेशों की मात्रा की उसी मात्रा पर सेनवेट प्रत्यय कर लेगा जो शुल्क योग्य माल के विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित है।

(3) पृथक् लेखों को न रखने के लिए विकल्प चुनने वाला विनिर्माता निम्नलिखित शर्तों में से किसी शर्त, जो उसे लागू हो, का पालन करेगा, अर्थात्

(क) यदि छूट प्राप्त माल निम्नलिखित है—

- (i) टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय 40 के अंतर्गत आने वाले पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले यानों पर प्रयुक्त किस्म के टायर या रहेड़ी और उनकी ट्यूब ;
- (ii) उक्त पहली अनुसूची के शीर्ष सं. 84.01 के अंतर्गत आने वाले अखबारी कागज रोल या शीटों में;
- (iii) उक्त पहली अनुसूची के अध्याय 50 से 63 के अंतर्गत आने वाले अंतिम उत्पाद है;

विनिर्माता, ऐसे अंतिम उत्पादों के, उनके कारखाने से निकाले जाने के समय, विनिर्माण में या इसके संबंध में प्रयुक्त निवेशों के सेनवेट के समतुल्य रकम का संदाय करेगा; या

(ख) यदि छूट प्राप्त माल शर्त (क) में वर्णित माल से भिन्न है तो विनिर्माता, छूट प्राप्त अंतिम उत्पाद के विक्रय के लिए उनकी कारखाने से निकासी के समय विनिर्माता द्वारा प्रभारित कुल कीमत के, जिसमें बिक्री कर तथा अन्य कर, यदि कोई हो, सम्मिलित नहीं हो, आठ प्रतिशत के बराबर रकम का संदाय करेगा।

स्पष्टीकरण : शर्त (क) और (ख) में उल्लिखित रकम विनिर्माता द्वारा सेनवेट प्रत्यय नामे करके या अन्यथा संदत्त की जाएगी।

(4) ऐसी पूंजी माल पर, जिन्हें ऐसे अंतिम उत्पादों से, जिन्हें किसी अधिसूचना के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क में छूट प्राप्त है और जहां ऐसी छूट किसी वित्तीय वर्ष में निकासी की गई वस्तु के मूल्य या मात्रा पर आधारित है, भिन्न छूट प्राप्त माल के विनिर्माण में अनन्य रूप से उपयोग किया जाता है, कोई प्रत्यय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(5) उपनियम (1), उपनियम (2) उपनियम (3) और (4) के उपबंध उस दशा में लागू नहीं होंगे जहां छूट प्राप्त माल की निकासी या आपूर्ति निम्नलिखित में से किसी को की गई है—

- (i) मुक्त व्यापार जोन में स्थित कोई इकाई, या;
- (ii) विशेष आर्थिक जोन में स्थित कोई इकाई, या;
- (iii) शत प्रतिशत निर्यात-मुख्य उपक्रम, या;
- (iv) किमी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नालोजी पार्क या सॉफ्टवेयर टेक्नालोजी पार्क में स्थित कोई इकाई, या;
- (v) संयुक्त राष्ट्र या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या उनके द्वारा वित्तपोषित परियोजना को उनके शासकीय उपयोग के लिए किया गया प्रदाय जिस पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिमूचना सं. 108/95-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 28 अगस्त, 1995 के अधीन उपलब्ध शुल्क की छूट उपलब्ध है; या
- (vi) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सं. 2) नियम, 2001 के उपबंधों के निबंधनों में ब्रांड के अधीन निर्यात के लिए।

7. **दस्तावेज और लेखा**—(1) विनिर्माता द्वारा सेनवेट प्रत्यय, निम्नलिखित में से किसी भी दस्तावेज के आधार पर लिया जाएगा, अर्थात् :—

(क) निम्नलिखित द्वारा जारी बीजक,—

- (I) किसी विनिर्माता द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सं. 2) नियम, 2001 के उपबंधों के निबंधनों में निम्नलिखित की निकामी के लिए—
 - (I) उसके कारखाने या उसके डिपो या उक्त विनिर्माता के परेपण अधिकर्ता के परिसर या किसी ऐसे अन्य परिसर से, जहां माल की उक्त विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से बिक्री की जाती है, निवेश या पूंजी माल की;
 - (II) निवेश या पूंजी माल;
- (II) किसी आयातकर्ता;
- (III) किसी आयातकर्ता द्वारा उसके डिपो से या उक्त आयातकर्ता के परेपण अधिकर्ता के परिसरों से, यदि यथास्थिति, उक्त डिपो या परिसर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2001 के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत है;
- (IV) किसी प्रथम प्रक्रम वाले व्यौहारी या द्वितीय प्रक्रम वाले व्यौहारी;
- (ख) किसी विनिर्माता या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सं. 2) नियम, 2001 के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार निवेश अथवा पूंजी माल के आयातकर्ता द्वारा, ऐसे मामले में जहां सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों की अतिरिक्त रकम या अतिरिक्त सीमा शुल्क का संदाय कर दिया गया है, ऐसे मामलों को छोड़ कर जहां शुल्क की अतिरिक्त रकम, विनिर्माता निवेश अथवा पूंजी माल के आयातकर्ता से कपट, दुस्संधि, या जानबूझकर किया गया मिथ्या कथन या तथ्य छिपाए जाने या अधिनियम अथवा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) अथवा तद्धीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का शुल्क के संदाय के अपवंचन के आशय से उल्लंघन के कारण उद्ग्रहीत नहीं की गई या कम उद्ग्रहीत की गई, उसके कारखाने या उसके डिपो या उक्त विनिर्माता अथवा आयातकर्ता के परेपण अधिकर्ता के परिसर या ऐसे किसी अन्य परिसर से जहां बीजक; उक्त विनिर्माता अथवा आयातकर्ता द्वारा या उनकी ओर से माल की बिक्री की जाती है, जारी अनुपूरक, बीजक;
- (ग) प्रवेश पत्र।

(2) निवेश या पूंजी माल पर सेनवेट प्रत्यय लेने वाली विनिर्माता या उत्पादक यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे निवेश और पूंजी माल, जिनकी बाबत उसने/सेनवेट प्रत्यय लिया है, ऐसे माल हैं, जिन पर माल के साथ लगे दस्तावेजों में यथा उपदर्शित समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय कर दिया गया है, सभी युक्तियुक्त उपाय करेगा।

स्पष्टीकरण—ऐसे किसी विनिर्माता या उत्पादक की जो उसके द्वारा प्राप्त किए गए निवेशों या पूंजी माल पर सेनवेट प्रत्यय से रहा है तभी यह समझा जाएगा कि उसने युक्ति युक्त उपाय किए हैं, यदि उसका स्वयं का निम्नलिखित में से किसी के द्वारा, नियम 7 में विनिर्दिष्ट, यथास्थिति उत्पादशुल्क या अतिरिक्त सीमा शुल्क का साक्ष्य देने वाले दस्तावेज को जारी करने वाले, यथास्थिति विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता की पहचान और पते की बाबत समाधान हो जाता है,—

- (क) उसकी व्यक्तिगत जानकारी; या
- (ख) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके हस्ताक्षर या हस्ताक्षर से वह परिचित है, दिए गए प्रमाणपत्र के सामर्थ्य पर; या
- (ग) ऐसे किसी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक द्वारा, जिसकी अधिकारिता के भीतर ऐसे विनिर्माता का कारखाना है या आपूर्तिकर्ता के कारबार का स्थान है, यथास्थिति, विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता को जारी प्रमाणपत्र के सामर्थ्य पर और जब विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता की पहचान और पते का समाधान किसी प्रमाण पत्र की सामर्थ्य पर दिया जाता है वहां सेनवेट के प्रत्यय लेने वाला विनिर्माता या उत्पादक ऐसे प्रमाणपत्र की मांग पर उचित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए प्रतिधारित करेगा।

(3) प्रथम प्रक्रम या द्वितीय प्रक्रम व्यवहारी से क्रय किए गए निवेशों या पूंजी माल की बाबत सेनवेट प्रत्यय केवल तब अनुज्ञात किया जाएगा जब ऐसे व्यवहारी के यह तथ्य उपदर्शित करते हुए अभिलेख रखे हैं कि निवेश या पूंजी माल ऐसे स्टॉक से प्रदाय किए गए थे जिस पर ऐसे निवेश या पूंजी माल के उत्पादक द्वारा शुल्क संदत्त की गई थी और केवल अनुपातिक आधार पर ऐसी शुल्क के संदाय की रकम उसके द्वारा बीजक में उपदर्शित की गई है।

(4) अंतिम उत्पादों का विनिर्माता निवेशों और पूंजीमाल की प्राप्ति निपटान, उपभोग और तालिका के लिए ऐसे उचित अभिलेख रखेगा जिसमें मूल्य संदत्तशुल्क ऐसे व्यक्ति जिससे निवेश और पूंजी माल क्रय किया गया है से संबंधित सुसंगत जानकारी अभिलिखित की जाती है और सेनवेट प्रत्यय की स्वीकार्यता संबंधी सबूत का भार ऐसा प्रत्यय लेने वाले विनिर्माता पर होगा।

(5) अंतिम उत्पादों का विनिर्माता प्रत्येक मास की समाप्ति से पांच दिन के भीतर, इन नियमों से संलग्न प्ररूप में एक मासिक विवरणी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण—किसी वित्तीय वर्ष में निकासियों के मूल्य का मात्रा पर आधारित किसी छूट का उपभोग करने वाले विनिर्माता की बाबत, इस उपनियम के उपबंध उस वित्तीय वर्ष में इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "मास" पद के स्थान पर "तिमाही" पद रखा गया हो।

8. **सेनवेट प्रत्यय का अंतरण**—(1) यदि अंतिम उत्पादों का विनिर्माता अपना कारखाना किसी अन्य स्थल पर अन्तरित करता है या कारखाना स्वामित्व में परिवर्तन के कारण अथवा कारखाने के विक्रय, विलयन, आमेसन, पट्टे ऐसे कारखाने के दायित्व के अंतरण के लिए विनिर्दिष्ट उपबंध के साथ किसी संयुक्त उद्यम के मददे अंतरित होता है तो विनिर्माता ऐसे अंतरित, विक्रीत, विलयित, पट्टे पर दिए गए या आमेलित कारखाने में उसके खातों में पड़े उपयोग न किए गए सेनवेट प्रत्यय को अंतरित करने की अनुज्ञा दी जाएगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन सेनवेट प्रत्यय का अंतरण तभी अनुज्ञात किया जाएगा जब निवेशों का स्टॉक, उसी रूप में या प्रक्रिया के अंतर्गत या पूंजी माल भी कारखाने के साथ नए स्थान या स्वामित्व को अंतरित किया जाता है और निवेशों, या पूंजी माल, जिस पर प्रत्यय का उपभोग किया जाता है, आयुक्त के समाधान रूप में सम्यक् रूप से लेखा में लिए जाते हैं।

9. **संक्रमण कालीन उपबंध**—(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944, जैसे कि वे 1 जुलाई 2001 के पूर्व विद्यमान थे के अधीन विनिर्माता द्वारा अर्जित प्रत्यय की कोई राशि और उस दिन शेष अनप्रयुक्त राशि इन नियमों के अधीन ऐसे विनिर्माता को सेनवेट प्रत्यय के रूप में अनुज्ञात होगी और इन नियमों के अनुसार उपयोग किये जाने के लिए अनुज्ञात की जायेगी।

(2) ऐसे विनिर्माता को, जो किसी वित्तीय वर्ष में निकासियों के मूल्य या मात्रा के आधार पर किसी अधिसूचना के अधीन उसके द्वारा विनिर्मित उत्पाद शुल्क उदग्रहण्य माल के संपूर्ण शुल्क से छूट के लिए विकल्प देता है और जो ऐसे विकल्प का प्रयोग किए जाने के पूर्व निवेशों पर संदत्त शुल्क के प्रत्यय का उपभोग करता रहा है उस तारीख को जब ऐसे विकल्प का प्रयोग किया जाता है, स्टॉक में पड़े या स्टॉक में पड़े किन्हीं अंतिम उत्पादों के प्रयुक्त निवेशों की बाबत उसको अनुज्ञात सेनवेट प्रत्यय, यदि कोई है, के समतुल्य रकम का संदाय करना होगा और उसके खाते में शेष अतिशेष से, यदि कोई है, व्यपगत हो जाएगा और किसी अन्य उत्पाद शुल्क माल पर, चाहे उसकी निकासी बरेलू उपयोग के लिए की गई हो अथवा निर्यात के लिए, शुल्क के संदाय के लिए उपयोग किए जाने हेतु अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

10. **उत्तरपूर्वी प्रदेश के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अवस्थित कारखानों में विनिर्मित निवेशों की बाबत विशेष प्रबंध**—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी जब किसी विनिर्माता ने कोई निवेश या पूंजी माल, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 32/99 या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999 या अधिसूचना सं. 33/99 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999 के विबंधनों के अनुसार निकासी की है, वहां ऐसे निवेश या पूंजी माल पर सेनवेट प्रत्यय इस प्रकार अनुज्ञेय होगा मानो ऐसे निवेश या पूंजी माल पर संदत्त शुल्क का कोई भाग उक्त अधिसूचनाओं में से किसी के अधीन छूट प्राप्त नहीं था।

11. **समझे गए प्रत्यय के लिए माल को अधिसूचित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति**—नियम 3 में किसी बात के होते हुए भी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे निवेश घोषित कर सकेगी जिन पर संदत्त उत्पाद शुल्क या अतिरिक्त सीमा-शुल्क या अतिरिक्त सीमा-शुल्क ऐसी दर पर या ऐसी रकम के समतुल्य जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए संदत्त किया गया समझा जाएगा और ऐसे शुल्क का प्रत्यय, ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए संदत्त किया गया समझा जाएगा और ऐसे शुल्क का अनुज्ञात सेनवेट प्रत्यय ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, संदत्त किया गया समझा जाएगा भले ही घोषित निवेशों का उक्त अधिसूचना में घोषित अंतिम उत्पादों के विनिर्माता द्वारा मीधे प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि वे उक्त अंतिम उत्पादों में समाविष्ट हैं।

12. **गलत ढंग से लिए गए प्रत्यय की वसूली**—जब सेनवेट प्रत्यय गलत ढंग से लिया या उपयोग किया गया हो तो वह ब्याज सहित विनिर्माता में वसूल किया जाएगा और अधिनियम की धारा 11क, ख के उपबंध ऐसी वसूली करने के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

13. **अधिग्रहण और शास्ति**—(1) यदि कोई व्यक्ति ढंग से निवेशों या पूंजी माल की बाबत सेनवेट यह सुनिश्चित करने के लिए या युक्ति-युक्त उपाय किए बिना लेता है कि नियम 7 में विनिर्दिष्ट निवेशों या पूंजी माल से संलग्न दस्तावेजों में यथा उपदर्शित उक्त निवेश या पूंजी माल पर समुचित शुल्क संदत्त किया गया है या किसी निवेश या पूंजी माल की बाबत इन नियमों के उपबंधों में से किसी उपबंध का अतिलंघन करता है तब ऐसा सभी माल अधिग्रहण का दायी होगा और ऐसा व्यक्ति उत्पाद शुल्क माल पर जिनकी बाबत अतिलंघन किया गया है, शुल्क से अनधिक की शास्ति का या दस हजार रुपए का जो भी अधिक हो दायी होगा।

(2) यदि, सेनवेट प्रत्यय, कपट जान बूझकर दिए मिथ्याकथन, या दुरभि संधि या तथ्यों के छिपाने या अधिनियम के उपबंधों में से या तद्धीन बनाए गए नियमों में किसी उपबंध के अतिलंघन के शुल्क के संदाय से बचने के आशय से गलत ढंग से लिया गया है या उपयोग किया गया है तब विनिर्माता अधिनियम की धारा 11क ग के उपबंधों के विबंधनों के अनुसार शास्ति का संदाय करने का भी दायी होगा।

(3) उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा आदेश, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए, जारी किए जायेंगे।

उपाबंध (नियम 7 देखिए)

सेनबेट प्रत्यय नियम, 2001 के नियम 7 के अधीन मासिक विवरणी के लिए प्रोफार्मा

विनिवेश

क्रम सं.	दस्तावेज की प्रकार	दस्तावेज की सं. और तारीख	प्रदायकर्ता का नाम	प्रदायकर्ता का प्रकार	प्रदायकर्ता का ई.सी. सी. संख्या	वह तारीख जिसको निवेश प्राप्त किया गया	मूल्य	लिखे गये प्रत्यय के ब्यौरे						दस्तावेजों में मुख्य मद के लिए		
								सेनबेट	एस.ई. डी.	ए.ई.डी. (टी.टी.ए.)	ए.ई.डी. (जी. एस. आई.)	अतिरिक्त शुल्क	अन्य	वर्णन	उपशीर्ष	मन्त्र

पूजी माल

क्रम सं.	दस्तावेज की प्रकार	दस्तावेज की सं. और तारीख	प्रदायकर्ता का नाम	प्रदायकर्ता का प्रकार	प्रदायकर्ता का ई.सी. सी. संख्या	वह तारीख जिसको निवेश प्राप्त किया गया	मूल्य	लिखे गये प्रत्यय के ब्यौरे						दस्तावेजों में मुख्य मद के लिए		
								सेनबेट	एस.ई. डी.	ए.ई.डी. (टी.टी.ए.)	ए.ई.डी. (जी. एस. आई.)	अतिरिक्त शुल्क	अन्य	वर्णन	उपशीर्ष	मन्त्र

- यह उपदर्शित करें कि क्या बीजक, प्रवेशपत्र या कोई अन्य दस्तावेज है या नहीं।
- यह उपदर्शित करें कि क्या विनिर्माता, प्रथम प्रक्रम व्यवहारी है, द्वितीय प्रक्रम व्यवहारी है या आयातकर्ता है या नहीं।
- दस्तावेज के अंतर्गत आने वाले माल का पूर्ण मूल्य उपदर्शित करें।
- ऐसी मद के संबंध में ब्यौरे दे जिस पर बीजक के अंतर्गत अधिकतम शुल्क लगा है।

उद्घरण

क. निवेश प्रत्यय

	आरंभिक अतिशेष	मास के दौरान लिया गया प्रत्यय	मास के दौरान उपभोग किया गया प्रत्यय	अंतिम अतिशेष
सेनबेट				
एस.ई.डी.				
ए.ई.डी. (टी.टी.ए.)				
ए.ई.डी. (जी.एस.आई.)				
अतिरिक्त शुल्क				
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)				

ख. पूजी माल प्रत्यय

	आरंभिक अतिशेष	मास के दौरान लिया गया प्रत्यय	मास के दौरान उपभोग किया गया प्रत्यय	अंतिम अतिशेष
सेनबेट				
एस.ई.डी.				
ए.ई.डी. (टी.टी.ए.)				
ए.ई.डी. (जी.एस.आई.)				
अतिरिक्त शुल्क				
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)				

निर्धारित या अनुज्ञात हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम

पद

निर्धारित का सील

[फा. सं. 354/66/2001-टी.आर.यू.]

टी.आर. रुस्तगी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2001

No. 31/2001-CENTRAL EXCISE (N. T.)

G.S.R. 445(E).— In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) These rules may be called the CENVAT Credit Rules, 2001.
(2) They extend to the whole of India.
(3) They shall come into force on and from the 1st day of July, 2001.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Act" means the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944);
- (b) "capital goods" means,-

- (i) all goods falling under Chapter 82, Chapter 84, Chapter 85, Chapter 90, heading No. 68.02 and sub-heading No. 6801.10 of the First Schedule to the Tariff Act;
- (ii) components, spares and accessories of the goods specified at (i) above;
- (iii) moulds and dies;
- (iv) refractories and refractory materials;
- (v) tubes and pipes and fittings thereof;
- (vi) pollution control equipment; and
- (vii) storage tank,

used in the factory of the manufacturer of the final products, but does not include any equipment or appliance used in an office;

- (c) "exempted goods" means goods which are exempt from the whole of the duty of excise leviable thereon, and includes goods which are chargeable to "Nil" rate of duty;

- (d) "final products" means excisable goods manufactured or produced from inputs, except matches;

- (e) "first stage dealer" means a dealer who purchases the goods directly from,-

- (i) the manufacturer under the cover of an invoice issued in terms of the provisions of Central Excise (No. 2) Rules, 2001 or from the depot of the said manufacturer, or from premises of the consignment agent of the said manufacturer or from any other premises from where the goods are sold by or on behalf of the said manufacturer, under cover of an invoice; or

- (ii) an importer or from the depot of an importer or from the premises of the consignment agent of the importer, under cover of an invoice;

- (f) "input" means all goods, except high speed diesel oil and motor spirit, commonly known as petrol, used in or in relation to the manufacture of final products whether directly or indirectly and whether contained in the final product or not, and includes lubricating oils, greases, cutting oils, coolants, accessories of the final products cleared along with the final product, goods used as paint, or as packing material, or as fuel, or for

generation of electricity or steam used for manufacture of final products or for any other purpose, within the factory of production.

Explanation 1.- The high speed diesel oil or motor spirit, commonly known as petrol, shall not be treated as an input for any purpose whatsoever.

Explanation 2.- Inputs include goods used in the manufacture of capital goods which are further used in the factory of the manufacturer;

(g) "manufacturer" or "producer" in respect of goods falling under Chapter 62 of the said First Schedule shall include a person who is liable to pay the duty of excise leviable on such goods under sub-rule (3) of rule 4 of the Central Excise (No. 2) Rules, 2001;

(h) "Tariff Act" means the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986);

(i) "second stage dealer" means a dealer who purchases the goods from a first stage dealer;

(j) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. CENVAT credit.- (1) A manufacturer or producer of final products shall be allowed to take credit (hereinafter referred to as the CENVAT credit) of -

- (i) the duty of excise specified in the First Schedule to the Tariff Act, leviable under the Act;
- (ii) the duty of excise specified in the Second Schedule to the Tariff Act, leviable under the Act;
- (iii) the additional duty of excise leviable under section 3 of the Additional Duties of Excise (Textile and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978);
- (iv) the additional duty of excise leviable under section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957);
- (v) the Nation 1 Calamity Contingent duty leviable under section 136 of the Finance Act, 2001 (14 of 2001); and
- (vi) the additional duty leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), equivalent to the duty of excise specified under clauses (i), (ii), (iii), (iv) and (v) above,

paid on any inputs or capital goods received in the factory on or after the first day of July, 2001, including the said duties paid on any inputs used in the manufacture of intermediate products, by a job-worker availing the benefit of exemption specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 214/86- Central Excise, dated the 25th March, 1986, published in the Gazette of India vide number GSR 547 (E), dated the 25th March, 1986, and received by the manufacturer for use in, or in relation to, the manufacture of final products, on or after the first day of July, 2001.

Explanation.- For the removal of doubts it is clarified that the manufacturer of the final products shall be allowed CENVAT credit of additional duty leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) on goods falling under heading No. 98.01 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the manufacturer or producer of final products shall be allowed to take CENVAT credit of the duty paid on inputs lying in stock or in process or inputs contained in the final products lying in stock on the date on which any goods cease to be exempted goods or any goods become excisable.

(3) The CENVAT credit may be utilized for payment of any duty of excise on any final products or for payment of duty on inputs or capital goods themselves if such inputs are removed as such or after being partially processed, or such capital goods are removed as such:

Provided that while paying duty, the CENVAT credit shall be utilised only to the extent such credit is available on the fifteenth day of a month for payment of duty relating to the first fortnight of the month, and the last day of a month for payment of duty relating to the second fortnight of the month or in case of a manufacturer availing exemption by notification based on value of clearances in a financial year, for payment of duty relating to the entire month.

(4) When inputs or capital goods, on which CENVAT credit has been taken, are removed as such from the factory, the manufacturer of the final products shall pay an amount equal to the duty of excise which is leviable on such goods at the rate applicable to such goods on the date of such removal and on the value determined for such goods under section 4 or section 4A of the Act, as the case may be, and such removal shall be made under the cover of an invoice referred to in rule 7.

(5) The amount paid under sub-rule (4) shall be eligible as CENVAT credit as if it was a duty paid by the person who removed such goods under sub-rule (4).

(6) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1),-

(a) CENVAT credit in respect of inputs or capital goods produced or manufactured ,-

- (i) in a free trade zone or a special economic zone and used in the manufacture of the final products in any other place in India; or
- (ii) by a hundred per cent. export-oriented undertaking or by a unit in an Electronic Hardware Technology Park or Software Technology Park and used in the manufacture of the final products in any place in India,

shall be restricted to the extent which is equal to the additional duty leviable on like goods under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) paid on such inputs or capital goods;

(b) CENVAT credit in respect of -

- (i) the additional duty of excise under section 3 of the Additional Duties of Excise (Textile and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978);
- (ii) the additional duty of excise under section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957);
- (iii) the National Calamity Contingent duty under section 136 of the Finance Act, 2001 (14 of 2001); and
- (iv) the additional duty under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), equivalent to the duty of excise specified under clauses (i), (ii) and (iii) above,

shall be utilized only towards payment of duty of excise leviable under the said Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, or under the said Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, or the National Calamity Contingent duty under the said section 136 of the Finance Act, 2001(14 of 2001) respectively, on any final products manufactured by the manufacturer or for payment of such duty on inputs themselves if such inputs are removed as such or after being partially processed;

(c) The CENVAT credit, in respect of additional duty leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), paid on marble slabs or tiles falling under sub-heading No. 2504.21 or 2504.31 respectively of the First Schedule to the Tariff Act shall be allowed to the extent of thirty rupees per square metre;

(d) The CENVAT credit of the duty paid on the inputs shall not be allowed in respect of texturised yarn (including draw-twisted or draw-wound yarn) of polyesters falling under heading No. 54.02 of the First Schedule to the Tariff Act, manufactured by an independent texturiser, that is to say, a manufacturer engaged in the manufacture of texturised yarn (including draw-twisted or draw-wound yarn) of polyesters falling under heading No. 54.02, who does not have the facility in his factory (including plant and machinery) for manufacture of partially oriented yarn of polyesters falling under sub-heading No. 5402.42 of the First Schedule to the Tariff Act.

Explanation.- Where the provisions of any other rule or notification provide for grant of partial or full exemption on condition of non-availability of credit of duty paid on any input or capital goods, the provisions of such other rule or notification shall prevail over the provisions of these rules.

4. Conditions for allowing CENVAT credit.- (1) The CENVAT credit in respect of inputs may be taken immediately on receipt of the inputs in the factory of the manufacturer:

Provided that in respect of final products falling under Chapter 62 of the First Schedule to the Tariff Act, the CENVAT credit of duty paid on inputs may be taken immediately on receipt of such inputs in the registered premises of the person who gets such final products manufactured on his account on job work subject to the condition that such inputs are used in the manufacture of such final products by the job worker

(2) (a) The CENVAT credit in respect of capital goods received in a factory at any point of time in a given financial year shall be taken only for an amount not exceeding fifty per cent. of the duty paid on such capital goods in the same financial year;

(b) The balance of CENVAT credit may be taken in any financial year subsequent to the financial year in which the capital goods were received in the factory of the manufacturer, if the capital goods, other than components, spares and accessories, refractories and refractory materials and goods falling under heading No. 68.02 and sub-heading No. 6801.10 of the First Schedule to the Tariff Act, are in the possession and use of the manufacturer of final products in such subsequent years.

Illustration.- A manufacturer received machinery on April 16, 2001 in his factory. CENVAT of two lakh rupees is paid on this machinery. The manufacturer can take credit upto a maximum of one lakh rupees in the financial year 2001-2002, and the balance in subsequent years.

(3) The CENVAT credit in respect of the capital goods shall be allowed to a manufacturer even if the capital goods are acquired by him on lease, hire purchase or loan agreement, from a financing company.

(4) The CENVAT credit in respect of capital goods shall not be allowed in respect of that part of the value of capital goods which represents the amount of duty on such capital goods, which the manufacturer claims as depreciation under section 32 of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961).

(5) (a) The CENVAT credit shall be allowed even if any inputs or capital goods as such or after being partially processed are sent to a job worker for further processing, testing, repair, re-conditioning or any other purpose, and it is established from the records, challans or memos or any other document produced by the assessee taking the CENVAT credit that the goods are received back in the factory within one hundred and eighty days of their being sent to a job worker and if the inputs or the capital goods are not received back within one hundred eighty days, the manufacturer shall pay an amount equivalent to the CENVAT credit attributable to the inputs or capital goods by debiting the CENVAT credit or otherwise, but the manufacturer can take the CENVAT credit again when the inputs or capital goods are received back in his factory.

(b) The CENVAT credit shall also be allowed in respect of jigs, fixtures, moulds and dies sent by a manufacturer of final products to a job worker for the production of goods on his behalf and according to his specifications.

(6) The Commissioner of Central Excise having jurisdiction over the factory of the manufacturer of the final products who has sent the inputs or partially processed inputs outside his factory to a job-worker may, by an order, which shall be valid for a financial year, in respect of removal of such inputs or partially processed inputs, and subject to such conditions as he may impose in the interest of revenue including the manner in which duty, if leviable, is to be paid, allow final products to be cleared from the premises of the job-worker.

5. Refund of CENVAT credit.- Where any inputs are used in the final products which are cleared for export under bond or letter of undertaking, as the case may be, or used in the intermediate products cleared for export, the CENVAT credit in respect of the inputs so used shall be allowed to be utilized by the manufacturer towards payment of duty of excise on any final products cleared for home consumption or for export on payment of duty and where for any reason such adjustment is not possible, the manufacturer shall be allowed refund of such amount subject to such safeguards, conditions and limitations as may be specified by the Central Government by notification in the Official Gazette:

Provided that no refund of credit shall, be allowed if the manufacturer avails of drawback allowed under the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1995, or claims a rebate of duty under the Central Excise (No. 2) Rules, 2001, in respect of such duty.

6. Obligation of manufacturer of dutiable and exempted goods.- (1) The CENVAT credit shall not be allowed on such quantity of inputs which is used in the manufacture of exempted goods, except in the circumstances mentioned in sub-rule (2).

(2) Where a manufacturer avails of CENVAT credit in respect of any inputs, except inputs intended to be used as fuel, and manufactures such final products which are chargeable to duty as well as exempted goods, then, the manufacturer shall maintain separate accounts for receipt, consumption and inventory of inputs meant for use in the manufacture of dutiable final products and the quantity of inputs meant for use in the manufacture of exempted goods and take CENVAT credit only on that quantity of inputs which is intended for use in the manufacture of dutiable goods.

(3) The manufacturer, opting not to maintain separate accounts shall follow either of the following conditions, as applicable to him, namely:-

(a) if the exempted goods are-

- (i) tyres of a kind used on animal drawn vehicles or handcarts and their tubes, falling within Chapter 40 of the First Schedule to the Tariff Act;
- (ii) newsprint, in rolls or sheets, falling within heading No.48.01 of the said First Schedule;
- (iii) final products falling within Chapters 50 to 63 of the said First Schedule,

the manufacturer shall pay an amount equivalent to the CENVAT credit attributable to inputs used in, or in relation to, the manufacture of such final products at the time of their clearance from the factory; or

- (b) if the exempted goods are other than those described in condition (a), the manufacturer shall pay an amount equal to eight per cent. of the total price, excluding sales tax and other taxes, if any, paid on such goods, of the exempted final product charged by the manufacturer for the sale of such goods at the time of their clearance from the factory.

Explanation.- The amount mentioned in conditions (a) and (b) shall be paid by the manufacturer by debiting the CENVAT credit or otherwise.

(4) No CENVAT credit shall be allowed on capital goods which are used exclusively in the manufacture of exempted goods, other than the final products which are exempt from the whole of the duty

of excise leviable thereon under any notification where exemption is granted based upon the value or quantity of clearances made in a financial year.

(5) The provisions of sub-rule (1), sub-rule (2), sub-rule (3) and sub-rule (4) shall not be applicable in case the exempted goods are either-

- (i) cleared to a unit in a free trade zone; or
- (ii) cleared to a unit in a special economic zone; or
- (iii) cleared to a hundred per cent. export-oriented undertaking; or
- (iv) cleared to a unit in an Electronic Hardware Technology Park or Software Technology Park; or
- (v) supplied to the United Nations or an international organization for their official use or supplied to projects funded by them, on which exemption of duty is available under notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.108/95-Central Excise, dated 28th August, 1995; or
- (vi) cleared for export under bond in terms of the provisions of the Central Excise (No. 2) Rules, 2001.

7. Documents and accounts.- (1) The CENVAT credit shall be taken by the manufacturer on the basis of any of the following documents, namely :-

(a) an invoice issued by-

(i) a manufacturer for clearance of -

(I) inputs or capital goods from his factory or from his depot or from the premises of the consignment agent of the said manufacturer or from any other premises from where the goods are sold by or on behalf of the said manufacturer;

(II) inputs or capital goods as such;

(ii) an importer;

(iii) an importer from his depot or from the premises of the consignment agent of the said importer if the said depot or the premises, as the case may be, is registered in terms of the provisions of Central Excise (No. 2) Rules, 2001;

(iv) a first stage dealer or a second stage dealer,

in terms of the provisions of Central Excise (No. 2) Rules, 2001;

(b) a supplementary invoice, issued by a manufacturer or importer of inputs or capital goods in terms of the provisions of Central Excise (No. 2) Rules, 2001 from his factory or from his depot or from the premises of the consignment agent of the said manufacturer or importer or from any other premises from where the goods are sold by, or on behalf of, the said manufacturer or importer, in case additional amount of excise duties or additional duty of customs leviable under section 3 of Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) has been paid, except where the additional amount of duty became recoverable from the manufacturer or importer of inputs or capital goods on account of any non-levy or short-levy by reason of fraud, collusion or any wilful mis-statement or suppression of facts or contravention of any provisions of the Act or of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) or the rules made thereunder with intent to evade payment of duty;

(c) a bill of entry.

(2) The manufacturer or producer taking CENVAT credit on inputs or capital goods shall take all reasonable steps to ensure that the inputs or capital goods in respect of which he has taken the CENVAT credit are goods on which the appropriate duty of excise as indicated in the documents accompanying the goods, has been paid.

Explanation.- The manufacturer or producer taking CENVAT credit on inputs or capital goods received by him shall be deemed to have taken reasonable steps if he satisfies himself about the identity and address of the manufacturer or supplier, as the case may be, issuing the document specified in rule 7, evidencing the payment of excise duty or the additional duty of customs, as the case may be, either-

(a) from his personal knowledge; or

(b) on the strength of a certificate given by a person with whose handwriting or signature he is familiar; or

(c) on the strength of a certificate issued to the manufacturer or the supplier, as the case may be, by the Superintendent of Central Excise within whose jurisdiction such manufacturer has his factory or the supplier has his place of business,

and where the identity and address of the manufacturer or the supplier is satisfied on the strength of a certificate, the manufacturer or producer taking CENVAT credit shall retain such certificate for production before the proper officer on demand.

(3) The CENVAT credit in respect of inputs or capital goods purchased from a first stage or second stage dealer shall be allowed only if such dealer has maintained records indicating the fact that the inputs or capital goods were supplied from the stock on which duty was paid by the producer of such inputs or capital goods and only an amount of such duty on pro rata basis has been indicated in the invoice issued by him.

(4) The manufacturer of final products shall maintain proper records for the receipt, disposal, consumption and inventory of the inputs and capital goods in which the relevant information regarding the value, duty paid, the person from whom the inputs or capital goods have been purchased is recorded and the burden of proof regarding the admissibility of the CENVAT credit shall lie upon the manufacturer taking such credit.

(5) The manufacturer of final products shall submit within five days from the close of each month to the Superintendent of Central Excise, a monthly return in the form annexed to these rules.

Explanation.- In respect of a manufacturer availing of any exemption based on the value or quantity of clearances in a financial year, the provisions of this sub-rule shall have effect in that financial year as if for the expression "month", the expression "quarter" was substituted.

8. Transfer of CENVAT credit.- (1) If a manufacturer of the final products shifts his factory to another site or the factory is transferred on account of change in ownership or on account of sale, merger, amalgamation, lease or transfer of the factory to a joint venture with the specific provision for transfer of liabilities of such factory, then, the manufacturer shall be allowed to transfer the CENVAT credit lying unutilized in his accounts to such transferred, sold, merged, leased or amalgamated factory.

(2) The transfer of the CENVAT credit under sub-rule (1) shall be allowed only if the stock of inputs as such or in process, or the capital goods is also transferred alongwith the factory to the new site or ownership and the inputs, or capital goods, on which credit has been availed of are duly accounted for to the satisfaction of the Commissioner.

9. Transitional provision.- (1) Any amount of credit earned by a manufacturer under the Central Excise Rules, 1944 as they existed prior to the 1st day of July, 2001 and remaining unutilised on that day shall be allowable as CENVAT credit to such manufacturer under these rules, and be allowed to be utilised in accordance with these rules.

(2) A manufacturer who opts for exemption from the whole of the duty of excise leviable on goods manufactured by him under a notification based on the value or quantity of clearances in a financial year, and who has been taking CENVAT credit on inputs before such option is exercised, shall be required to pay an amount equivalent to the CENVAT credit, if any, allowed to him in respect of inputs lying in stock or used in any final products lying in stock on the date when such option is exercised and after deducting the said amount from the balance, if any, lying in his credit, the balance, if any, still remaining shall lapse and shall not be allowed to be utilized for payment of duty on any excisable goods, whether cleared for home consumption or for export.

10. Special dispensation in respect of inputs manufactured in factories located in specified areas of North East region.- Notwithstanding anything contained in these rules, where a manufacturer has cleared any inputs or capital goods, in terms of notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 32/99- Central Excise, dated the 8th July, 1999, or notification No. 33/99- Central Excise, dated the 8th July, 1999, the CENVAT credit on such inputs or capital goods shall be admissible as if no portion of the duty paid on such inputs or capital goods was exempted under any of the said notifications.

11. Power of Central Government to notify goods for deemed CENVAT credit.- Notwithstanding anything contained in rule 3, the Central Government may, by notification in the Official Gazette declare the inputs on which the duties of excise, or additional duty of customs paid, shall be deemed to have been paid at such rate or equivalent to such amount as may be specified in the said notification and allow CENVAT credit of such duty deemed to have been paid in such manner and subject to such conditions as may be specified in the said notification even if the declared inputs are not used directly by the manufacturer of final products declared in the said notification, but are contained in the said final products.

12. Recovery of CENVAT credit wrongly taken.- Where the CENVAT credit has been taken or utilized wrongly, the same along with interest shall be recovered from the manufacturer and the provisions of sections 11A and 11AB of the Act shall apply mutatis mutandis for effecting such recoveries.

13. Confiscation and penalty.- (1) If any person, takes CENVAT credit in respect of inputs or capital goods, wrongly or without taking reasonable steps to ensure that appropriate duty on the said inputs or capital goods has been paid as indicated in the document accompanying the inputs or capital goods specified in rule 7, or contravenes any of the provisions of these rules in respect of any inputs or capital goods, then, all such goods shall be liable to confiscation and such person, shall be liable to a penalty not exceeding the duty on the excisable goods in respect of which any contravention has been committed, or ten thousand rupees, whichever is greater.

(2) In a case, where the CENVAT credit has been taken or utilized wrongly on account of fraud, willful mis-statement, collusion or suppression of facts, or contravention of any of the provisions of the Act or the rules made thereunder with intention to evade payment of duty, then, the manufacturer shall also be liable to pay penalty in terms of the provisions of section 11AC of the Act.

(3) Any order under sub-rule (1) or sub-rule (2) shall be issued by the Central Excise Officer following the principles of natural justice.

Annexure (see rule 7)

PROFORMA FOR MONTHLY RETURN UNDER RULE 7 OF THE CENVAT Credit Rules, 2001

INPUTS

I. No.	Type of document ¹	No. and date of document	Name of the supplier	Type of supplier ²	ECC No of the supplier	Date on which inputs received	Value ³	Details of credit taken						For the main item in the document ⁴		
								CENVAT	SED	AED (TTA)	AED (GSI)	Addl. Duty	Other	Description	Sub-heading	Qty.

CAPITAL GOODS

I. No.	Type of document ¹	No. and Date of Document	Name of the supplier	Type of supplier ²	ECC No of the supplier	Date on which capital goods received	Value ³	Details of credit Taken						For the main item in the document ⁴		
								CENVAT	SED	AED (TTA)	AED (GSI)	Addl. Duty	Other	Description	Sub-heading	Qty.

1. Indicate whether invoice, Bill of Entry or any other document
2. Indicate whether manufacturer, first stage dealer, second stage dealer or importer
3. Indicate full value of the goods covered by the document
4. Give details with respect to the item with maximum duty covered by the invoice

ABSTRACT*A. INPUT CREDIT*

	OPENING BALANCE	CREDIT TAKEN DURING THE MONTH	CREDIT UTILIZED DURING THE MONTH	CLOSING BALANCE
CENVAT				
SED				
AED (TTA)				
AED (GSI)				
ADDL. DUTY				
OTHER (pl. specify)				

B. CAPITAL GOODS CREDIT

	OPENING BALANCE	CREDIT TAKEN DURING THE MONTH	CREDIT UTILIZED DURING THE MONTH	CLOSING BALANCE
CENVAT				
SED				
AED (TTA)				
AED (GSI)				
ADDL. DUTY				
OTHER (pl. specify)				

Place:

Date:

Signature of the assessee or the authorised signatory
Name in capital letters
Designation
Seal of the assessee

[F. No. 354/66/2001-TRU]

T. R. RUSTAGI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2001

सं. 32/2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 446(अ).—केन्द्रीय सरकार, उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद (अपील) नियम, 2001 है।
 - (2) इनका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।
 - (3) ये तारीख 1 जुलाई, 2001 से ही प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—
 - (क) "अधिनियम" से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) अभिप्रेत है;
 - (ख) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है।
 - (ग) इन नियमों में प्रयोग किए गए उन शब्दों और पदों का जो परिभाषित नहीं हैं लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं; क्रमशः वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुद्दिष्ट किया गया है।
3. आयुक्त (अपील) को आवेदन का प्ररूप—(1) अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन अपील, आयुक्त (अपील) को प्ररूप सं. ड.क.-1 में की जाएगी।
 - (2) अपील के आधार और प्ररूप सं. ड.क.-1 में यथा अंतर्विष्ट सत्यापन का प्ररूप,—
 - (क) किसी व्यक्ति की दशा में, स्वयं व्यक्ति द्वारा या व्यक्ति के भारत से अनुपस्थित रहने पर, संबंधित व्यक्ति द्वारा या इस निमित्त व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा; और यदि व्यक्ति अप्राप्तवय है या अपने मामले संभालने के लिए मानसिक रूप से सक्षम है तो उसके संरक्षक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम है;
 - (ख) हिन्दू अधिभक्त कुटुम्ब की दशा में, कर्ता द्वारा और कर्ता के भारत से अनुपस्थित या अपने मामले संभालने के लिए मानसिक रूप से अक्षम रहने पर उक्त कुटुम्ब के किसी अन्य वयस्क सदस्य द्वारा;
 - (ग) कंपनी या स्थानीय प्राधिकरण की दशा में, उसके प्रधान अधिकारी द्वारा;
 - (घ) फर्म की दशा में, उसके किसी भागीदार द्वारा जो अप्राप्तवय नहीं है;
 - (ङ) किसी अन्य संगम की दशा में, संगम के किसी सदस्य द्वारा या उसके प्रधान अधिकारी द्वारा; और
 - (च) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।
 - (3) प्ररूप सं. ड.क.-1 में अपील का प्ररूप दो प्रतियों में फाइल किया जायेगा और उसके साथ विनिश्चय या आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई है, प्रति संलग्न की जाएगी।
4. आयुक्त (अपील) को आवेदन का प्ररूप—(1) अधिनियम की धारा 35ड की उपधारा (4) के अधीन आवेदन प्ररूप सं. ड.क.-2 में किया जायेगा।
 - (2) आवेदन का प्ररूप, प्ररूप सं. ड.क.-2 में दो प्रतियों में फाइल किया जायेगा और उसके साथ न्याय निर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित विनिश्चय या आदेश की प्रमाणित प्रति तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा, प्राधिकारी को आयुक्त (अपील) को आवेदन करने का निदेश करते हुए किए गए आदेश की प्रति संलग्न की जाएगी।
5. अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य की प्रस्तुति.—(1) अपीलार्थी आयुक्त (अपील) के समक्ष कोई अतिरिक्त साक्ष्य लिखित या मौखिक सिवाय उन साक्ष्यों के जिन्हें उसने न्याय निर्णायक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया हो केवल निम्नलिखित परिस्थितियों के अलावा:—(क) जहां न्याय निर्णायक अधिकारी ने साक्ष्य को, जिसे स्वीकार किया जाना चाहिये, अस्वीकृत किया हो; या

(ख) यदि अपीलार्थी पर्याप्त कारण से, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है, यद्यपि उसे न्याय निर्णायक प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था; या

(ग) यदि अपीलार्थी, पर्याप्त कारण से, जो अपील के लिए सुसंगत आधार है, कोई साक्ष्य न्याय निर्णायक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका था; या

(घ) यदि न्याय निर्णायक प्राधिकारी ने, अपीलार्थी को अपील के किसी आधार से सुसंगत साक्ष्य देने का पर्याप्त अवसर दिए बिना, आदेश किया है जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है।

(2) जब तक आयुक्त (अपील) लिखित में अपील की मंजूरी के लिए कारण अभिलिखित न करे उपनियम (1) के अधीन कोई साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाएगा।

(3) आयुक्त (अपील) उपनियम (1) के अधीन कोई साक्ष्य ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि न्याय निर्णायक प्राधिकारी या उक्त प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को,

(क) अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य या दस्तावेज की जांच की किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने; या

(ख) अपीलार्थी द्वारा उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत किये गए साक्ष्य की काट में किसी साक्ष्य या कोई साक्षी प्रस्तुत करने, का पर्याप्त अवसर अनुज्ञात नहीं किया जाए।

(4) इन नियम में अंतर्निहित कोई बात, अपील निपटाने के लिए, आयुक्त (अपील) की, किसी दस्तावेज को पेश करने या किसी साक्षी की परीक्षा करने के लिए, निदेश देने की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी।

6. अपील अधिकरण को की जाने वाली अपील, आदि का प्ररूप,—(1) अधिनियम की धारा 35 ख की उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण को की जाने वाली अपील प्ररूप सं. ड.क.-3 में की जाएगी।

(2) अधिनियम की धारा 35 ख की उपधारा (4) के अधीन अपील अधिकरण को किए जाने वाले प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन प्ररूप सं. ड.क.-4 में किया जाएगा।

(1) जब केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 35 ख की उपधारा (1) के अधीन कोई अपील की जाती है या उस धारा की उपधारा (4) के अधीन प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन दिया जाता है तो, अपील के आधारों, प्रत्याक्षेपों के आधारों और यथास्थिति प्ररूप सं. ड.क.-3 और प्ररूप सं. ड.क.-4 से यथा अंतर्निष्ठ सत्यापन के प्ररूपों पर, नियम 3 के उपनियम (2) से विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा क्रमशः हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(2) प्ररूप सं. ड.क.-3 से अपील का प्ररूप और प्ररूप सं. ड.क.-4 से प्रत्याक्षेपों के ज्ञापन का प्ररूप चार प्रतियों में फाइल किए जाएंगे और उनके साथ आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, प्रतियाँ समान संख्या में (जिनमें कम से कम एक प्रमाणित प्रति होनी चाहिए) संलग्न की जाएगी।

7. अपील अधिकरण को किए जाने वाले आवेदन का प्ररूप—(1) अधिनियम की धारा 35 ड की उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण को किया जाने वाला आवेदन प्ररूप सं. ड.क.-5 में किया जाएगा।

(2) प्ररूप सं. ड.क.-5 में आवेदन का प्ररूप चार प्रतियों में फाइल किया जाएगा और उसके साथ में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा पारित विनिश्चय या आदेश की प्रतियाँ समान संख्या में (जिनमें कम से कम एक प्रमाणित प्रति होगी) और ऐसे आयुक्त को अपील अधिकरण में आवेदन का निदेश करते हुए बोर्ड द्वारा पारित आदेश की एक प्रति संलग्न की जाएगी।

8. उच्च न्यायालय को किए जाने वाले आवेदन का प्ररूप—(1) अधिनियम की धारा 35 ज की उपधारा (1) के अधीन उच्च न्यायालय में अपील अधिकरण को किसी विधि के प्रश्न का निर्देश उच्च न्यायालय को किए जाने का निदेश करने की अपेक्षा करते हुए आवेदन प्ररूप सं. ड.क.-5 में किया जाएगा और उक्त आवेदन चार प्रतियों में फाइल किया जाएगा।

(2) अधिनियम की धारा 35 ज की उपधारा (3) के अधीन उच्च न्यायालय को दिए जाने वाला प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन प्ररूप सं. ड.क.-7 में दिया जाएगा और उक्त ज्ञापन चार प्रतियों में फाइल किया जाएगा।

(3) जब अधिनियम की धारा 35 ज की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन या उस धारा की उपधारा (3) के अधीन प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है तो प्ररूप सं. ड क-6 या प्ररूप सं. ड क-7 में यथा अंतर्विष्ट आवेदन ज्ञापन या सत्यापन का प्ररूप यथास्थिति नियम 3 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

8. केन्द्रीय सरकार को किए जाने वाले पुनरीक्षण आवेदन का प्ररूप अधिनियम—(1) धारा 35ड की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार को किया जाने वाला पुनरीक्षण आवेदन प्ररूप सं. ड क-8 में किया जाएगा।

(2) प्ररूप ड क-8 में यथा अंतर्विष्ट पुनरीक्षण आवेदन के आधार और सत्यापन का प्ररूप नियम 3 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

(3) पुनरीक्षण आवेदन अपीलार्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने की दशा में प्रतिनिधि को, अपीलार्थी की ओर हस्ताक्षर करने और उपस्थित होने को प्राधिकृत करने वाला दस्तावेज उक्त पुनरीक्षण आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा।

(4) प्ररूप ड क-8 में पुनरीक्षण आवेदन का प्ररूप दो प्रतियों में फाइल किया जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की दो प्रतियां संलग्न की जाएगी, अर्थात् :—

(i) अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट आदेश : और

(ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा पारित किया गया विनिश्चय या आदेश जो इस उपनियम के खंड (i) में निर्देश किए गए आदेश की विषय वस्तु था।

10. पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए जाने की प्रक्रिया—(1) पुनरीक्षण आवेदन, प्ररूप ड क-8 में अवर सचिव, पुनरीक्षण आवेदन एकक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथा तल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जाएगा या ऐसे अधिकारी को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा।

(2) उपनियम 1 अधीन रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा गया पुनरीक्षण आवेदन उस तारीख को ऐसे अवर सचिव को दिया गया समझा जाएगा जिसको वह ऐसे अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया गया था।

11. अपील, आदि फाइल किए जाने की प्रक्रिया—(1) प्ररूप सं. ड क-3 में कोई अपील या प्ररूप सं. ड क-4 या प्ररूप सं. ड क-7 में प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन या प्ररूप सं. ड क-5 या प्ररूप सं. ड क-6 में आवेदन रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत की जाएगी, या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा रजिस्ट्रार या ऐसे अधिकारी के पते पर भेजी जाएगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन डाक द्वारा भेजी गई अपील, या प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन या आवेदन उस तारीख को जिसको यथास्थिति रजिस्ट्रार के कार्यालय या ऐसे अधिकारी के कार्यालय में वह प्राप्त किया जाता है, रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।

12. प्राधिकृत प्रतिनिधियों के लिए अर्हताएं—अधिनियम की धारा 35 थ की उपधारा (2) के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकृत प्रतिनिधि के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास निम्नलिखित अर्हताओं में से कोई एक है, अर्थात् :—

(क) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम में, 1949 (1949 का 38) के अर्थान्तर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट ; या

(ख) लागत और संकर्म अकाउंटेंट अधिनियम, 1959 (1959 का 23) अर्थान्तर्गत लागत अकाउंटेंट ; या

(ग) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) के अर्थान्तर्गत कंपनी सचिव जिसने उस अधिनियम की धारा 6 के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है ; या

(घ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर या आनर्स डिग्री धारक अथवा कारबार प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा धारक ; या

(ङ) सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग या स्वापक विभाग में पूर्ण नियोजित व्यक्ति जिसने उक्त विभागों में एक या अधिक में किमी हैसियत में कुल मिलाकर कम से कम दस वर्ष की सेवा करने के पश्चात् ऐसे नियोजन से सेवानिवृत्ति ले ली है या पद त्याग दिया है।

स्पष्टीकरण :—इस नियम में “मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय” से, नीचे विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालयों में से कोई एक अभिप्रेत है; अर्थात् :—

- (i) भारतीय विश्वविद्यालय :—
भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निगमित कोई भारतीय विश्वविद्यालय
- (ii) रंगून यूनिवर्सिटी
- (iii) इंगलिस और वेल्स यूनिवर्सिटी
(बरमिंघम, ब्रिस्टल, कैमिडज, डरहम, लीड्स, लिबरपूल, लंदन, मानचेस्टर, आक्सफोर्ड रीडिंग, शेफील्ड और वेल्स यूनिवर्सिटी)
- (iv) स्कॉटिश यूनिवर्सिटी
अवेर्दीन, एडिनबर्ग, ग्लासगो और सेन्ट एन्ड्रयूज यूनिवर्सिटी
- (v) आयरिश यूनिवर्सिटी
डबलिन (ट्रिन्टी कालेज) यूनिवर्सिटी, क्वीन यूनिवर्सिटी, बेलफास्ट और नेशनल यूनिवर्सिटी आफ डबलिन
- (vi) पाकिस्तान यूनिवर्सिटी
तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा निगमित कोई पाकिस्तानी विश्वविद्यालय
- (vii) बंगलादेश यूनिवर्सिटी
तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा निगमित कोई बंगलादेश विश्वविद्यालय

13. धारा 35 फ (5) ख के अधीन प्राधिकारी: उन कार्यवाहियों में अधिकारिता रखने वाला केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त जिनमें ऐसा व्यक्ति जो विधि व्यवसायी नहीं है, अधिनियम के अधीन कार्यवाही के संबंध में कदाचार का दोषी पाया जाता है, अधिनियम की धारा 35 फ की उपधारा (5) के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए प्राधिकारी होगा।

परिशिष्ट

प्ररूप सं. डक-1

(नियम 3 देखिए)

धारा 35 के अधीन आयुक्त (अपील) को अपील करने का प्ररूप

सं. तारीख 2001

- आवेदक का नाम और पता
- उस विनिश्चय या आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को पारित करने वाले अधिकारी का पदनाम और पता और विनिश्चय या आदेश की तारीख
- अपीलार्थी को उस विनिश्चय या आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, संसूचना की तारीख।
- पता जिस पर अपीलार्थी को सूचना भेजी जाए।
- (i) माल का वर्णन और वर्गीकरण।
(ii) विवाद की अवधि
(iii) मद (ii) में उल्लिखित अवधि के लिए मांगी गई शुल्क की रकम, यदि कोई हो
(iv) मद (i) में उल्लिखित अवधि के लिए दावा की गई प्रतिदाय की रकम, यदि कोई हो
(v) अधिरोपित जुर्माने की रकम
(vi) अधिरोपित शास्ति की रकम
(vii) अभिग्रहीत माल का बाजार मूल्य

6. क्या शुल्क या शान्ति या दोनों जमा किए जाते हैं या नहीं, यदि नहीं तो क्या ऐसे निक्षेप से छूट प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन किया गया है (ऐसे खालान की एक प्रति जिसके अधीन निक्षेप किया जाता है, प्रस्तुत किया जायेगा)।
7. क्या अपीलार्थी व्यक्तिगत रूप से सुने जाने की वांछा करता है या नहीं।
8. अपील में दावाकृत।

अनुतोष

तथ्यों का विवरण

अपील के आधार

प्राधिकृत प्रतिनिधि

यदि कोई हो, के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं अपीलार्थी घोषणा करता हूँ कि जो भी ऊपर कथन किया गया है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आज तारीख को सत्यापित।

स्थान

तारीख

प्राधिकृत प्रतिनिधि,

यदि कोई हो, के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पण :— (1) अपील के आधार और सत्यापन के प्ररूप पर नियम 3 के उपबंधों के अनुसार अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये।

(2) अपील का प्ररूप जिसके अंतर्गत तथ्यों का विवरण और अपील का आधार भी सम्मिलित है, दो प्रतियों में फाइल किया जायेगा और जिससे उस विनिश्चय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की एक प्रति संलग्न होगी।

प्ररूप सं. डक-2

(नियम 4 देखिए)

अधिनियम की धारा 35 ड की उपधारा (4) के अधीन आयुक्त (अपील) को आवेदन करने के लिए प्ररूप

सं.....तारीख.....2001

आवेदक

बनाम

प्रत्यर्थी

1. आवेदक का पदनाम और पता (यदि आवेदक न्यायनिर्णयन प्राधिकारी नहीं है तो आवेदन करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त से प्राधिकार की एक प्रति संलग्न करनी चाहिए)
2. प्रत्यर्थी का नाम और पता
3. विनिश्चय या आदेश, जिसकी बाबत यह आवेदन किया जा रहा है, पारित करने वाले अधिकारी का पदनाम और पता
4. वह तारीख जिसको धारा 35ड की उपधारा (1) के अधीन आदेश बोर्ड द्वारा पारित किया गया है
5. न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के उपरोक्त (3) में निर्दिष्ट आदेश की संसूचना की तारीख
6. (i) साल का वर्णन और वर्गीकरण

- (ii) विवाद की अवधि
 - (iii) स्तंभ (ii) से उल्लिखित अवधि के लिए मांगी गई शुल्क की रकम, यदि कोई हो
 - (iv) स्तंभ (1) में उल्लिखित अवधि के लिए दावा की गई प्रतिदाय की रकम, यदि कोई हो
 - (v) अधिरोपित जुर्माने की रकम
 - (vi) अधिरोपित शास्ति की रकम
 - (vii) अभिग्रहीत माल का बाजार मूल्य
7. आवेदन पत्र दावाकृत अनुतोष

तथ्यों का विवरण

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदन का आधार

टिप्पणी :—आवेदन का प्ररूप जिसमें आवेदन के तथ्यों के विवरण और आधार सम्मिलित हैं दो प्रतियों में फाइल किया जाएगा और जिसके साथ न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पारित विनिश्चय या आदेश की दो प्रतियां (जिनमें से एक कम से कम प्रमाणित प्रति होगी) और अधिनियम की धारा 35ड की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त की एक प्रति संलग्न होगी।

प्ररूप सं. डक-3

(नियम 6 देखिए)

अधिनियम की धारा 35 ख के अधीन अपील अधिकरण को अपील करने का प्ररूप सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण)

अपील अधिकरण

अपील सं. तारीख 2001

..... अपीलार्थी

बनाम

..... प्रत्यर्थी

1. आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पारित करने वाले प्राधिकारी का पदनाम और पता।
2. आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई, की संख्या और तारीख।
3. आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई, की प्रति की संसूचना की तारीख।
4. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और कमीशनरी जिसमें निर्धारण/शास्ति जुर्माने का आदेश/विनिश्चय किया गया था।
5. उन दशाओं में न्यायनिर्णयन प्राधिकारी का पदनाम और पता जहां वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, आयुक्त (अपील) का आदेश है।
6. पता जिस पर अपीलार्थी को सूचना भेजी जा सके।
7. पता जिस पर प्रत्यर्थी को सूचना भेजी जा सकेगी।
8. क्या उस विनिश्चय या आदेश में, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, निर्धारण के प्रयोजनों के लिए उत्पाद शुल्क की दर या माल के मूल्य से संबंध रखने वाला कोई प्रश्न अंतर्वर्तित है या नहीं, यथास्थिति शुल्क या अंतर्वर्तित शुल्क का अंतर, जुर्माना या अंतर्वर्तित शास्ति की रकम या अंतर्वर्तित माल का मूल्य।
9. (i) माल का वर्णन और वर्गीकरण
- (ii) विवाद की अवधि
- (iii) मद (ii) से उल्लिखित अवधि के लिए मांगी गई शुल्क की रकम, यदि कोई हो
- (iv) मद (i) में उल्लिखित अवधि के लिए दावा की गई प्रतिदाय की रकम, यदि कोई हो

(v) अधिरोपित जुर्माने की रकम

(vi) अधिरोपित शास्ति की रकम

(vii) अभिग्रहीत माल की बाजार मूल्य

10. क्या उत्पाद शुल्क या शास्ति निक्षेप की जाती है या नहीं : यदि, नहीं तो क्या ऐसे निक्षेप से छूट प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन किया गया है या नहीं (चालान की एक प्रति जिसके अधीन निक्षेप किया जाता है; प्रस्तुत की जायेगी)

11. क्या अपीलार्थी व्यक्तिगत रूप से सुने जाने की बांछा करता है या नहीं

12. अपील में दावाकृत

अनुतोष

तथ्यों का विवरण

अपील के आधार

प्राधिकृत प्रतिलिपि,

यदि कोई हो, के हस्ताक्षर

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं अपीलार्थी की यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो भी कथन किया गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आज तारीख 2001 को सत्यापित

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

प्राधिकृत प्रतिनिधि

यदि कोई है, के हस्ताक्षर

टिप्पण :—यदि अपील केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है, अपील के आधार और सत्यापन के प्ररूप पर नियम 3 के अनुसार अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(2) अपील जिसमें तथ्यों के विवरण और अपील के आधार सम्मिलित हैं चार प्रतियों में फाइल की जायेगी और ऐसे आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की बराबर संख्या में प्रतियां (जिनमें से एक प्रति सत्यापित प्रति होगी) संलग्न होगी।

(3) अपील का प्ररूप अंग्रेजी (या हिंदी) में होगा और इसमें संक्षिप्ततः और सुभिन्न शीर्षों के अधीन किसी तर्क रहित या वर्णन रहित अपील के आधार उपवर्णित होने चाहिए तब ऐसे आधारों को क्रमवर्ती रूप से संख्यांकित किया जाना चाहिए।

1. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदत्त की जाने वाली दो सौ रुपये की फीस ऐसे स्थान पर जहां अधिकरण की न्यायपीठ स्थित है अवस्थित, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की किसी शाखा पर अधिकरण की न्यायपीठ के सहारे रजिस्ट्रार के पक्ष में जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संदत्त की जायेगी और डिमांड ड्राफ्ट अपील के प्ररूप के साथ संलग्न होगा।

प्ररूप सं. ड.क-4

[नियम 6 (2) देखिए]

अधिनियम की धारा 35 ख के अधीन अपील अधिकरण के प्रति आक्षेपों के ज्ञापन का प्ररूप सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (विध्वंश) अपील अधिकरण प्रति आक्षेप)

संख्या तारीख 2001 अपील सं. तारीख 2001 अपीली की

बनाम

..... प्रत्यर्थी

1. ऐसा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और कमीशनरी जिसमें निर्धारण/शास्ति जुर्माने का आदेश/विनिश्चय किया गया था।
2. यथास्थिति, अपीलार्थी या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा अपील अधिकरण में फाइल की गई अपील या आवेदन की सूचना की प्राप्ति की तारीख।
3. वह पता जहां प्रत्यर्थी को सूचना भेजी जा सकेगी।
4. वह पता जहां अपीलार्थी/आवेदक को सूचना भेजी जा सकेगी।
5. क्या ऐसे विनिश्चय या आदेश में, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, उत्पाद शुल्क की दर या निर्धारण के प्रयोजनों के लिए माल के मूल्य से संबंधित कोई प्रश्न अंतर्बलित है; यदि नहीं तो, यथास्थिति, शुल्क या अंतर्बलित शुल्क में अंतर या अंतर्बलित जुर्माने या शास्ति की रकम या अंतर्बलित माल का मूल्य।
6. (i) माल का वर्णन और वर्गीकरण
(ii) विवाद की अवधि
(iii) मंद (i) में वर्णित अवधि के लिए मांगे गए शुल्क की, यदि कोई हो, रकम
(iv) मद (i) में वर्णित अवधि के लिए दावा की गई प्रतिदाय की; यदि कोई हो, रकम
(v) अधिरोपित जुर्माने की रकम
(vi) अधिरोपित शास्ति की रकम
(vii) अभिग्रहीत माल का बाजार मूल्य।
7. प्रति आक्षेपों के ज्ञापन में दावा किया गया अनुतोष।

प्रति आक्षेप के आधार

प्रत्यर्थी के हस्ताक्षर

प्राधिकृत प्रतिनिधि के,
यदि कोई है, हस्ताक्षर।

सत्यापन

मैं प्रत्यर्थी, यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आज तारीख 2001 को सत्यापित

प्रत्यर्थी के हस्ताक्षर

प्राधिकृत प्रतिनिधि के
यदि कोई है, हस्ताक्षर

टिप्पण : (1) प्रति आक्षेपों के आधार और सत्यापन का प्ररूप प्रत्यर्थी द्वारा नियम 3 के उपबंधों के अनुसार हस्ताक्षरित किया जायेगा।

- (2) प्रति आक्षेपों के ज्ञापन का प्ररूप चार प्रतियों में फाइल किया जायेगा।
- (3) प्रति आक्षेपों के ज्ञापन का प्ररूप अंग्रेजी या हिंदी में होना चाहिए और इसमें प्रति आक्षेपों के आधार पर संक्षिप्त रूप में तथा सुभिन्न शीर्षों के अधीन किसी तर्क या वृत्तांत के बिना दिए जाने चाहिए और ऐसे आधारों को क्रमवार संख्यांकित किया जाना चाहिए।
- (4) अपील अधिकरण कार्यालय द्वारा तथा आवंटित अपील/आवेदन का संख्यांक और वर्ण को, जो प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्त की गई अपील/आवेदन की सूचना में वर्णित है, प्रत्यर्थी द्वारा भरा जाये।

प्ररूप सं. ड.क-5

(नियम 7 देखिए)

अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण को आवेदन का प्ररूप

सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण संख्या तारीख 2001 अपील सं.
 तारीख 2001
 आवेदक

बनाम

..... प्रत्यर्थी

1. आवेदक का पदनाम और पता (यदि आवेदक न्यायनिर्णयन प्राधिकारी नहीं है तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त से आवेदन करने के प्राधिकारी की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए)
2. प्रत्यर्थी का नाम और पता।
3. ऐसे विनिश्चय या आदेश को, जिसके संबंध में यह आवेदन किया जा रहा है, पारित करने वाले अधिकारी का पदनाम और पता तथा विनिश्चय या आदेश की तारीख।
4. ऐसा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और कमीशनरी जहां विनिश्चय या आदेश किया गया था।
5. ऐसी तारीख जिसको बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा 35ड की उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित किया गया है।
6. न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को ऊपर (3) में निर्दिष्ट आदेश की संसूचना की तारीख।
7. क्या ऐसे विनिश्चय या आदेश में, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, उत्पाद शुल्क की दर या निर्धारण के प्रयोजनों के लिए माल के मूल्य से संबंधित कोई प्रश्न अंतर्बलित है, यदि नहीं तो, यथास्थिति, शुल्क या अंतर्बलित शुल्क अंतर या अंतर्बलित जुर्माने या शास्ति की रकम या अंतर्बलित माल का मूल्य।
8. (i) माल का वर्णन और वर्गीकरण
 (ii) विवाद की अवधि
 (iii) स्तंभ (i) में वर्णित अवधि के लिए मांगी गई शुल्क की, यदि कोई है, रकम
 (iv) स्तंभ (1) में वर्णित अवधि के लिए दावा किये गये प्रतिदाय की; यदि कोई है, रकम
 (v) अधिरोपित जुर्माने की रकम
 (vi) अधिरोपित शास्ति की रकम
 (vii) अभिग्रहीत माल का बाजार मूल्य।
9. आवेदन में दावा किया गया अनुतोष।

तथ्यों का कथन

आवेदन के आधार

आवेदकों के हस्ताक्षर

प्राधिकृत प्रतिनिधि के,
 यदि कोई है, हस्ताक्षर।

टिप्पण : आवेदन का प्ररूप, जिसमें तथ्यों का कथन और आवेदन के आधार भी सम्मिलित हैं, चार प्रतियों में फाइल किया जाएगा और इसके साथ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा पारित निर्णय या आदेश की चार प्रतियां (जिनमें से कम से कम एक प्रति सत्यापित प्रति होगी) और बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश की एक प्रति होगी।

प्ररूप सं. डक-6

[नियम 8 (1) देखिए]

अधिनियम की धारा 35ज की उपधारा (1) के अधीन उच्च न्यायालय को आवेदन का प्ररूप

..... स्थित उच्च न्यायालय

अपील सं. (अपीलार्थी का नाम) के मामले में

आवेदन सं तारीख 2001.

(कार्यालय द्वारा भरा जाए)

..... आवेदक

बनाम

..... प्रत्यर्थी

1. ऐसा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और कमीशनरी जिससे आवेदन फाइल किया गया है ;
2. ऐसी अपील का संख्यांक जिससे निर्देश उद्भूत हुआ ;
3. ऐसा पता, जिस पर आवेदक को सूचना भेजी जा सकेगी ;
4. ऐसा पता, जिस पर प्रत्यर्थी को सूचना भेजी जा सकेगी ;
5. उपर्युक्त अपील, अपील अधिकरण की न्यायपीठ द्वारा तारीख को अधिनिर्णीत की गई थी ;
6. अधिनियम की धारा 35 ग के अधीन आदेश की सूचना की तारीख की कर दी गई थी ;
7. ऐसे तथ्य, जिन्हें स्वीकार किया गया था और/अपील अधिकरण द्वारा स्थापित किया गया और जो मामले का कथन करने के लिए आवश्यक हैं, तत्काल संदर्भ के लिए उपाबंध में कथित है ;
8. अपील अधिकरण के आदेश से विधि के निम्नलिखित प्रश्न उद्भूत हुए हैं ;
9. अतः आवेदक, अधिनियम की धारा 35 ग की उपधारा (1) के अधीन उच्च न्यायालय से यह अपेक्षा करता है कि उच्च न्यायालय, अपील अधिकरण को ऊपर पैरा 8 में निर्दिष्ट विधि के प्रश्नों को उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट करने के लिए निर्देश करे ;
10. नीचे विनिर्दिष्ट दस्तावेज या उनकी प्रतियां (जहां आवश्यक हो, दस्तावेजों के अंग्रेजी अनुवाद के साथ) मामले के कथन के साथ संलग्न हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्राधिकृत प्रतिनिधि के,
यदि कोई है, हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं..... आवेदक, यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर किए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

आज, तारीख..... 2001 को सत्यापित

आवेदक के हस्ताक्षर

प्राधिकृत प्रतिनिधि के,
यदि कोई है, हस्ताक्षर

टिप्पण :—(1) यदि आवेदन सीमा शुल्क आयुक्त से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है तो आवेदन और सत्यापन का प्ररूप नियम 3 के उपबंधों के अनुसार आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे:

1. आवेदन चार प्रतियों में फाइल किया जाएगा।
2. अधिनियम के उपबंधों के अधीन मंदाय किए जाने के लिए अपेक्षित 200 रु. की फीस, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पक्ष में, उस स्थान पर, जहां उच्च न्यायालय स्थित है, स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की किसी शाखा पर संदेय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से दी जाएगी और मांग ड्राफ्ट आवेदन के प्ररूप के साथ संलग्न किया जाएगा।

प्ररूप सं. डक-7

[नियम 8 (2) देखिए]

अधिनियम की धारा 35 ग की उपधारा (1) के अधीन उच्च न्यायालय को

आवेदन स्थित उच्च न्यायालय

प्रति आक्षेपों की ज्ञापन सं. तारीख 2000

(कार्यालय द्वारा भरा जाए)

आवेदन सं. तारीख 200

..... आवेदक

बनाम

..... प्रत्यर्थी

1. ऐसा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और कमीशनरी, जहां से प्रति आक्षेपों का ज्ञापन फाइल किया गया है :
2. उच्च न्यायालय में फाइल किए गए आवेदन की प्रत्यर्थी को प्राप्ति की तारीख :
3. ऐसा पता, जिस पर प्रत्यर्थी को सूचना भेजी जा सकेगी:
4. ऐसा पता, जिस पर आवेदक को सूचना भेजी जा सकेगी:
5. ऐसे तथ्य, जिन्हें स्वीकार किया गया था और अपील अधिकरण द्वारा स्थापित किया गया और जो मामले का कथन करने के लिए आवश्यक हैं, तत्काल संदर्भ के लिए उपाबंध में कथित है;
6. निम्नलिखित विधि के प्रश्न अपील अधिकरण के आदेश से उद्भूत होते हैं;
7. अतः अधिनियम की धारा 35 ज की उपधारा (1) के अधीन प्रत्यर्थी अपेक्षा करता है कि अधिकरण को उपरोक्त पैरा 6 में निर्दिष्ट विधि के प्रश्नों पर मामले के विवरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाए।
8. नीचे यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेज या उनकी प्रतियां (जहां आवश्यक हो, वहां दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद) मामले के विवरण के सभी उपाबंध हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्राधिकृत प्रतिनिधि के,
यदि कोई हो, के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, प्रत्यर्थी, यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आज तारीख 2001 को सत्यापित

आवेदक के हस्ताक्षर

प्राधिकृत प्रतिनिधि के,
यदि कोई हो, हस्ताक्षर

टिप्पण : (1) यदि ज्ञापन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा फाइल किया जाता है, तो प्रति आक्षेप के ज्ञापन का प्ररूप और प्रमाणन का प्ररूप नियम 3 के उपबंधों के अनुसार हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(2) प्रति आक्षेप का ज्ञापन चार प्रतियों में फाइल किया जाएगा।

प्ररूप सं. ऊ.क—8

(नियम 9 देखिए)

अधिनियम की धारा 35 ऊ.क के अधीन केन्द्रीय सरकार को पुनरीक्षण आवेदन करने का प्ररूप

पुनरीक्षण आवेदन सं. तारीख 2001

1. आवेदक का नाम और पता
2. वह आदेश, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया जाता है, पारित करने वाले आयुक्त (अपील) का पता
3. आदेश की सं. और तारीख
4. आदेश की संसूचना की तारीख
5. वह न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, जिसके विरुद्ध आयुक्त (अपील) द्वारा आदेश पारित किया गया है, का पदनाम और पता
6. पता जिस पर सूचनाएं/संसूचनाएं आवेदक को भेजी जा सकेंगी

7. क्या अपीलार्थी वैयक्तिक रूप से सुने जाने की वांछ करता है
8. (i) माल वर्गीकरण विवरण
- (ii) विवाद की अवधि
- (iii) मद (ii) में उल्लिखित अवधि के लिए मांगी गई शुल्क की रकम, यदि कोई हो
- (iv) मद (ii) में उल्लिखित अवधि के लिए दावा की गई प्रतिदाय की रकम, यदि कोई हो
- (v) अधिरोपित जुर्माने की रकम
- (vi) अधिरोपित शास्ति की रकम
- (vii) अभिग्रहीत माल का बाजार मूल्य
9. क्या शुल्क या शास्ति, यदि कोई हो, जमा की गई है या नहीं यथास्थिति, चालान/लेखा चालू की जिसके अधीन निक्षेप किया गया है,
10. आवेदक में दावा कृत अनुतोप

तथ्यों का विवरण

आवेदन के आधार

आवेदक के हस्ताक्षर

प्राधिकृत प्रतिनिधि

यदि कोई हो, के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, आवेदक, यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आज तारीख 2001 को सत्यापित

आवेदक के हस्ताक्षर

प्राधिकृत प्रतिनिधि के,

यदि कोई हो, के हस्ताक्षर

टिप्पण (1) आवेदन के आधार और सत्यापन का प्ररूप नियम 3 के उपनियम (2) विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(2) जहां आवेदन पत्र आवेदक के किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है, वहां आवेदक की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए और उपस्थित होने के लिए प्रतिनिधि को प्राधिकृत करने वाला दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न होगा।

(3) आवेदन पत्र जिसके अंतर्गत तथ्यों का विवरण और आवेदन के आधार भी सम्मिलित है, दो प्रतियों में फाइल किया जाएगा और वह आदेश जिसके विरुद्ध आवेदन फाइल किया जाता है और न्याय निर्णायक प्राधिकारी का वह विनिश्चय/आदेश भी जिसके विरुद्ध आयुक्त (आपील) ने आदेशपारित किया है, की समान संख्या में प्रतियां होंगी।

(4) आवेदन के प्ररूप अंग्रेजी (या हिन्दी) में होंगे और इसमें संक्षिप्ततः और सुभिन्न शीर्षों के अधीन किसी तर्क रहित या वृतांत रहित आवेदन के आधार उपवर्णित होने चाहिए तथा ऐसे आधारों को क्रमवर्ती रूप से संख्यांकित किया जाना चाहिए।

(5) अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदत्त की जाने वाली 200-00 रुपए की फीस टी. आर. 6 चालान के अधीन संदत्त की जाएगी और टी. आर. 6 चालान की दूसरी प्रति पुनरीक्षण के आवेदन के साथ फाइल की जाएगी।

[फा. सं. 354/66/2001-टीआरयू]

टी. आर. रुस्तागी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2001

No. 32/2001-CENTRAL EXCISE (N. T.)

G.S.R. 446(E).— In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) These rules may be called the Central Excise (Appeals) Rules, 2001.

(2) They extend to the whole of India.

(3) They shall come into force on and from the 1st day of July, 2001.
2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944);
 - (b) "Form" means a form appended to these rules;
 - (c) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
3. Form of appeal to Commissioner (Appeals).-(1) An appeal under sub-section (1) of section 35 of the Act to the Commissioner (Appeals) shall be made in Form No. E.A.-1.

(2) The grounds of appeal and the form of verification as contained in Form No. E.A.-1. shall be signed,-
 - (a) in the case of an individual, by the individual himself or where the individual is absent from India, by the individual concerned or by any person duly authorised by him in this behalf; and where the individual is a minor or is mentally incapacitated from attending to his affairs, by his guardian or by any other person competent to act on his behalf;
 - (b) in the case of a Hindu undivided family, by the Karta and, where the Karta is absent from India or is mentally incapacitated from attending to his affairs, by any other adult member of such family;
 - (c) in the case of a company or local authority, by the principal officer thereof;
 - (d) in the case of a firm, by any partner thereof, not being a minor;
 - (e) in the case of any other association, by any member of the association or the principal officer thereof; and

(f) in the case of any other person, by that person or any person competent to act on his behalf.

(3) The form of appeal in Form No. E.A.-1 shall be filed in duplicate and shall be accompanied by a copy of the decision or order appealed against.

4. Form of application to the Commissioner (Appeals).- (1) An application under sub-section (4) of section 35E of the Act to the Commissioner (Appeals) shall be made in Form No. E.A.-2.

(2) The form of application in Form No. E.A.-2 shall be filed in duplicate and shall be accompanied by a certified copy of the decision or order passed by the adjudicating authority and a copy of the order passed by the Commissioner of Central Excise directing such authority to apply to the Commissioner (Appeals).

5. Production of additional evidence before Commissioner (Appeals).- (1) The appellant shall not be entitled to produce before the Commissioner (Appeals) any evidence, whether oral or documentary, other than the evidence produced by him during the course of the proceedings before the adjudicating authority except in the following circumstances, namely:-

(a) where the adjudicating authority has refused to admit evidence which ought to have been admitted; or

(b) where the appellant was prevented by sufficient cause from producing the evidence which he was called upon to produce by adjudicating authority; or

(c) where the appellant was prevented by sufficient cause from producing before the adjudicating authority any evidence which is relevant to any ground of appeal; or

(d) where the adjudicating authority has made the order appealed against without giving sufficient opportunity to the appellant to adduce evidence relevant to any ground of appeal.

(2) No evidence shall be admitted under sub-rule (1) unless the Commissioner (Appeals) records in writing the reasons for its admission.

(3) The Commissioner (Appeals) shall not take any evidence produced under sub-rule (1) unless the adjudicating authority or an officer authorised in this behalf by the said authority has been allowed a reasonable opportunity,-

(a) to examine the evidence or document or to cross-examine any witness produced by the appellant; or

(b) to produce any evidence or any witness in rebuttal of the evidence produced by the appellant under sub-rule (1).

(4) Nothing contained in this rule shall affect the power of the Commissioner (Appeals) to direct the production of any document, or the examination of any witness, to enable him to dispose of the appeal.

6. Form of appeal, etc., to the Appellate Tribunal.- (1) An appeal under sub-section (1) of section 35B of the Act to the Appellate Tribunal shall be made in Form No. E.A.-3.

(2) A memorandum of cross-objections to the Appellate Tribunal under sub-section (4) of section 35B of the Act shall be made in Form No. E.A.-4.

(3) Where an appeal under sub-section (1) of section 35B of the Act or a memorandum of cross-objections under sub-section (4) of that section is made by any person other than the Commissioner of Central Excise, the grounds of appeal, the grounds of cross-objection and the forms of verification as

contained in Form Nos. E.A-3 and E.A-4, as the case may be, respectively shall be signed by the person specified in sub-rule (2) of rule 3.

(4) The form of appeal in Form No. E.A.-3 and the form of memorandum of cross-objections in Form No. E.A.-4 shall be filed in quadruplicate and shall be accompanied by an equal number of copies of the order appealed against (one of which at least shall be a certified copy).

7. Form of application to the Appellate Tribunal.- (1) An application under sub-section (1) of section 35E of the Act to the Appellate Tribunal shall be made in Form No. E.A.-5.

(2) The form of application in Form No. E.A.-5 shall be filed in quadruplicate and shall be accompanied by an equal number of copies of the decision or order passed by the Commissioner of Central Excise (one of which at least shall be a certified copy) and a copy of the order passed by the Board directing such application to the Appellate Tribunal.

8. Form of application to the High Court.- (1) An application under sub-section (1) of section 35H of the Act requiring the High Court to direct the Appellate Tribunal to the High Court any question of law shall be made in Form No. E.A.-6 and such application shall be filed in quadruplicate.

(2) A memorandum of cross-objections under sub-section (3) of section 35H of the Act to the High Court shall be made in Form No. E.A.-7 and such memorandum shall be filed in quadruplicate.

(3) Where an application under sub-section (1) of section 35H of the Act or a memorandum of cross-objections under sub-section (3) of that section is made by any person other than the Commissioner of Central Excise, the application, the memorandum or form of verification, as the case may be, contained in Form No. E.A.-6 or Form No. E.A.-7 shall be signed by the person specified in sub-rule (2) of Rule 3.

9. Form of revision application to the Central Government.- (1) A revision application under sub-section (3) of section 35EE of the Act to the Central Government shall be in Form No. E.A.-8.

(2) The grounds of revision application and the form of verification, as contained in Form E.A.-8, shall be signed by the person specified in sub-rule (2) of rule 3.

(3) Where the revision application is signed by the authorised representative of the applicant, the document authorising the representative to sign and appear on behalf of the applicant shall be appended to such revision application.

(4) The form of revision application in Form No. E.A.-8 shall be filed in duplicate and shall be accompanied by two copies of the following documents, namely:—

(i) order referred to in the first proviso to sub-section (1) of section 35B of the Act; and

(ii) decision or order passed by the Central Excise Officer, which was the subject matter of the order referred to in clause (i) of this sub-rule.

10. Procedure for filing revision application.- (1) The revision application in Form E.A.-8 shall be presented in person to the Under Secretary, Revision Application Unit, Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Sansad Marg, New Delhi-110 001, or sent by registered post to such officer.

(2) The revision application sent by registered post under sub-rule (1) shall be deemed to have been submitted to the said Under Secretary on the date on which it is received in the office of such officer.

11. Procedure for filling appeals etc.- (1) An appeal in Form No. E. A.-3 or a memorandum of cross-objections in Form No. E.A.-4 or Form No. E.A.-7 or an application in Form No. E.A.-5 or Form No.

E.A.-6 shall be presented in person to the Registrar or an officer authorized in his behalf by the Registrar, or sent by registered post addressed to the Registrar or such officer.

(2) An appeal or a memorandum of cross-objections or an application sent by post under sub-rule (1) shall be deemed to have been presented to the Registrar or to the officer authorized by the Registrar on the date on which it is received in the officer of the Registrar, or, as the case may be, in the office of such officer.

12. Qualifications for authorized representatives.- For the purposes of clause (c) of sub-section (2) of section 35Q of the Act, an authorized representative shall include a person who has acquired any of the following qualifications namely:-

(a) a Chartered Accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949); or

(b) a Cost Accountant within the meaning of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959); or

(c) a Company Secretary within the meaning of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980) who has obtained a certificate of practice under section 6 of that Act; or

(d) a post-graduate or an Honours degree holder in Commerce or a post-graduate degree or diploma holder in Business Administration from any recognised university; or

(e) a person formerly employed in the Department of Customs and Central Excise or Narcotics and has retired or resigned from such employment after having rendered service in any capacity in one or more of the said departments for not less than ten years in the aggregate.

Explanation.- In this rule "recognised University" means any of the Universities specified below, namely:-

I. Indian Universities

Any Indian University incorporated under any law for the time being in force in India;

II. Rangoon University;

III. English and Welsh Universities

The Universities of Birmingham, Bristol, Cambridge, Durham, Leeds, Liverpool, London, Manchester, Oxford, Reading, Sheffield and Wales;

IV. Scottish Universities

The Universities of Aberdeen, Edinburgh, Glasgow and St. Andrews;

V. Irish Universities

The Universities of Dublin (Trinity College), the Queen's University, Belfast and the National University of Dublin;

VI. Pakistan Universities

Any Pakistan University incorporated by any law for the time being in force;

VII. Bangladesh Universities

Any Bangladesh University incorporated by any law for the time being in force.

13. Authority under section 35Q (5) (b) of the Act.- The Commissioner of Central Excise having jurisdiction in the proceedings in which a person who is not a legal practitioner is found guilty of misconduct in connection with that proceeding under the Act shall be the authority for the purposes of clause (b) of sub-section (5) of section 35Q of the Act.

Appendix
Form No. EA-1
(see Rule 3)

Form of Appeal to the Commissioner (Appeals) under section 35 of the Act

1. No. of 2001
2. Name and address of the appellant.
3. Designation and address of the officer passing the decision or order appealed against and the date of the decision or order.
4. Date of communication of the decision or order appealed against to the appellant.
5. Address to which notices may be sent to the appellant.
6. (i) Description and classification of goods
(ii) Period of dispute
(iii) Amount of duty, if any, demanded for the period mentioned in item (ii)
(iv) Amount of refund if any claimed for the period mentioned in item (i)
(v) Amount of fine imposed.
(vi) Amount of penalty imposed
(vii) Market value of seized goods.
7. Whether duty or penalty or both is deposited; if not whether any application for dispensing with such deposit has been made. (A copy of the challan under which the deposit is made shall be furnished).
8. Whether the appellant wishes to be heard in person?
9. Reliefs claimed in appeal.

Statement of facts
Grounds of appeal

Signature of the authorised
Representative, if any

Signature of the applicant.

Verification

I.....the appellant,do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Verified today, theday of.....

Place.....

Date.....

Signature of the authorised
Representative, if any.

Signature of the appellant.

Note.- (1) The grounds of appeal and the form of verification shall be signed by the appellant in accordance with the provisions of rule 3.

(2) The form of appeal including the statement of facts and the grounds of appeal shall be filed in duplicate and shall be accompanied by a copy of the decision or order appealed against.

Form No. E.A-2

(see Rule 4)

Form of Application to the Commissioner (Appeals) under sub-section (4) of section 35E of the Act
No. of 2001
..... Applicant.

Vs

..... Respondent.

1. Designation and address of the applicant (If the applicant is not the adjudicating authority, a copy of the authorisation from the Commissioner of Central Excise to make the application should be enclosed).
2. Name and address of the respondent.
3. Designation and address of the officer passing the decision or order in respect of which this application is being made and the date of the decision or order.
4. Date on which order under sub-section (1) of section 35E has been passed by the Board.
5. Date of communication of the order referred to in (3) above in the adjudicating authority.
6. (i) Description and classification of goods
(ii) Period of dispute
(iii) Amount of duty, if any, demanded for the period mentioned in column (ii)
(iv) Amount of refund, if any, claimed for the period mentioned in column (ii)
(v) Amount of fine imposed
(vi) Amount of penalty imposed
(vii) Market value of seized goods.
6. Reliefs claimed in the application.

Statement of facts
Grounds of application

Signature of the applicant

Note.- The form of application including statement of facts and grounds of application shall be filed in duplicate and accompanied by two copies of the decision or order passed by the adjudicating authority (one of which at least shall be a certified copy) and a copy of the order of the Commissioner of Central Excise under sub-section (2) of section 35E of the Act.

Form No. E.A.-3

[See Rule 6]

Form of Appeal to Appellate Tribunal under section 35B of the Act
In the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal Appeal
No.....of.....2001.....Appellant.
Vs
.....Respondent.

1. The designation and address of the authority passing the order appealed against.
2. The number and date of the order appealed against.
3. Date of communication of a copy of the order appealed against.
4. State/Union territory and the Commissionerate in which the order/decision of assessment/penalty/fine was made.
5. Designation and address of the adjudicating authority in cases where the order appealed against is an order of the Commissioner (Appeals).
6. Address to which the notices may be sent to the appellant.
7. Address to which the notices may be sent to the respondent.
8. Whether the decision or order appealed against involves any question having a relation to the rate of duty of excise or to the value of goods for purposes of assessment or not; difference in duty or duty involved, or amount of fine or penalty involved or value of goods involved, as the case may be.
9. (i) Description and classification of goods
(ii) Period of dispute
(iii) Amount of duty, if any, demanded for the period mentioned in item (i)
(iv) Amount of refund, if any, claimed for the period mentioned in item (ii)
(v) Amount of fine imposed
(vi) Amount of penalty imposed
(vii) Market value of seized goods.
10. Whether duty or penalty is deposited; if not, whether any application for dispensing with such deposit has been made. (A copy of the challan under which the deposit is made shall be furnished).
11. Whether the appellant wishes to be heard in person?
12. Reliefs claimed in appeal.

Statement of facts
Grounds of appeal

Signature of the authorised
Representative, if any.

Signature of the Appellant

Verification

I,.....the appellant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Verified today, theday of.....2001.....

Signature of the authorised
Representative, if any.

Signature of the
Appellant.

Notes.- (1) The grounds of appeal and the form of verification shall, if the appeal is made by any person, other than the Commissioner of Central Excise be signed by the appellant in accordance with Rule 3.

(2) The appeal including the statement of facts and the grounds of appeal shall be filed in quadruplicate and shall be accompanied by an equal number of copies of the order appealed against (one of which at least shall be a certified copy).

(3) The form of appeal shall be in English (or Hindi) and should set forth, concisely and under distinct heads, the grounds of appeal without any argument or narrative and such grounds should be numbered consecutively.

(4) The fee of Rs. 200.00 required to be paid under the provisions of the Act shall be paid through a crossed bank draft drawn in favour of the Assistant Registrar of the Bench of the Tribunal on a branch of any nationalised bank located at the place where the Bench is situated and the demand draft shall be attached to the form of appeal.

Form No.E.A.-4

[See Rule 6(2)]

Form of Memorandum of Cross-objections to the Appellate Tribunal under section 35B of the Act

In the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal Cross-objection

No..... of 2001.....

In appeal No.....of 2001.....

.....Appellant

Vs

.....Respondent.

1. State/Union Territory and the Commissionerate in which the order/decision of assessment/penalty/fine was made.
2. Date of receipt of notice of appeal or application filed with the Appellate Tribunal by the appellant or as the case may be, the Commissioner of Central Excise.
3. Address to which notices may be sent to the respondent.
4. Address to which notices may be sent to the appellant/applicant.
5. Whether the decision or order appealed against involves any question having a relation to the rate of duty of excise or to the value of goods for purposes of assessment; if not, difference in duty or duty involved, or amount of fine or penalty involved or value of goods involved, as the case may be .
6. (i) Description and classification of goods
(ii) Period of dispute
(iii) Amount of duty, if any, demanded for the period mentioned in item (i)
(iv) Amount of refund, if any, claimed for the period mentioned in item (i)
(v) Amount of fine imposed

(vi) Amount of penalty imposed

(vii) Market value of seized goods.

6. **Reliefs claimed in the memorandum of cross-objections**
Grounds of Cross-objections

Signature of the authorised
Representative, if any.

Signature of the
Respondent.

Verification

I,.....the respondent, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Verified today, the.....day of.....2001.....

Signature of the authorised
Representative, if any.

Signature of the
Respondent.

Notes.- (1) The grounds of cross-objections and the form of verification shall be signed by the respondent in accordance with the provisions of Rule 3.

(2) The form of memorandum of corss-objections shall be filed in quadruplicate.

(3) The form of memorandum of cross-objections should be in English or Hindi and should set forth, concisely and under distinct heads the ground of the cross-objections without any argument or narrative and such grounds should be numbered consecutively.

(4) The number and year of appeal/application as allotted by the office of the Appellate Tribunal and appearing in the notice of appeal/application received by the respondent is to be filled in by the respondent.

Form No. E.A.-5

[See Rule 7]

Form of Application to Appellate Tribunal under sub-section (1) of section 35B of the Act
In the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal Appeal No.....of...2001.

.....Applicant

Vs.

.....Respondent.

1. Designation and address of the applicant (If the applicant is not the adjudicating authority, a copy of the authorisation from the Commissioner of Central Excise to make the application should be enclosed).
2. Name and address of the respondent.
3. Designation and address of the officer passing the decision or order in respect of which this application is being made and the date of the decision or order.
4. State/Union Territory and the Commissionerate in which the decision or order was made.
5. Date on which order under sub-section (1) of section 35E of the Act has been passed by the Board.
6. Date of communication of the order referred to in (3) above to the adjudicating authority..

7. Whether the decision or order appealed against involves any question having a relation to the rate of duty or excise or to the value of goods for purposes of assessment; if not, difference in duty or duty involved, or amount of fine or penalty involved or value of goods involved, as the case may be.
8. (i) Description and classification of goods
(ii) Period of dispute
(iii) Amount of duty, if any, demanded for the period mentioned in column (i)
(iv) Amount of refund, if any, claimed for the period mentioned in column (i)
(v) Amount of fine imposed
(vi) Amount of penalty imposed
(vii) Market value of seized goods.
9. Relief claimed in the application.

Statement of facts
Grounds of application

Signature of the authorised
representative, if any.

Signature of the applicant.

Note.- The form of application including the statement of facts and grounds of application shall be filed in quadruplicate and shall be accompanied by an equal number of copies of the decision or order passed by the Commissioner of Central Excise (one of which at least shall be a certified copy) and a copy of the order passed by the Board under sub-section (1) of section 35E of the Act.

Form No. E.A.-6
[See Rule 8 (1)]

Form of Application to the High Court under sub-section (1) of section 35H of the Act

In the High Court of Judicature at
In the matter of Appeal No. (Name of the appellant)
Application No.....of.....2001

(To be filled in by the Office)

.....Applicant.

Vs.

.....Respondent.

1. State or Union Territory and the Commissionerate from which the application is filed:
2. Number of the appeal which gives rise to the reference:
3. Address to which notices may be sent to the applicant:
4. Address to which notices may be sent to the respondent:
5. The appeal noted above was decided by theBench of the Appellate Tribunal on:
6. The notice of the order under section 35C of the Act was served on the applicant on:

7. The facts which are admitted and/or found by the Appellate Tribunal and which are necessary for drawing up a statement of the case are stated in the enclosure for ready reference:
8. The following questions of law arise out of the order of the Appellate Tribunal:
9. The applicant, therefore, requires under sub-section (1) of section 35H of the Act that the High Court directs the Appellate Tribunal to refer to the High Court the question of law referred to in paragraph 8 above.
10. The documents or copies thereof specified below (the translation in English of the documents, where necessary) are annexed with the statement of the case.

Signature of the authorised
representative, if any.

Signature of the applicant.

Verification

I,.....the applicant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Verified today, the.....day of.....2001.....

Signature of the authorised
representative, if any.

Signature of the applicant.

Notes.- (1) The application and the form of verification shall, if the application is made by any person, other than the Commissioner of Customs, be signed by the applicant in accordance with the provisions of Rule 3.

(2) The application shall be filed in quadruplicate.

(3) The fee of Rs. 200/- required to be paid under the provisions of the Act shall be through a crossed bank draft drawn in favor of the Registrar of the High Court on a branch of any nationalised bank located at the place where the High Court is situated and the demand draft shall be attached to the form of application.

Form No. E.A.-7

[See Rule 8(2)]

Form of Memorandum of Cross-Objections under sub-section (3) of section 35H of the Act in the matter of an application before the High Court under sub-section (1) of section 35 H of the Act

In the High Court of Judicature at

Memorandum of Cross-Objections No.....of.....2001.....

(To be filled in by the office)

In Application No.....of.....2001.....

.....Applicant.

Vs.

.....Respondent.

1. State or Union Territory and the Commissionerate from which the memorandum of cross-objection is filed;
2. Date of receipt of application filed with the High Court by the respondent:
3. Address to which notices may be sent to the respondent

4. Address to which notices may be sent to the applicant:
5. The facts which are admitted and/or found by the Appellate Tribunal and which are necessary for drawing up a statement of the case, are stated in the enclosure for ready reference:
6. The following questions of law arise out of the order of the Appellate Tribunal:
7. The respondent, therefore, requires under sub-section (1) of section 35H of the Act that the Tribunal may be directed to furnish a statement of the case on the questions of law referred to in paragraph 6 above.
8. That the documents or copies thereof as specified below (the translation in English of the documents where necessary) is annexed with the statement of case.

Signature of the authorised
representative, if any.

Signature of the applicant.

Verification

I,.....the respondent, do hereby declare tht what is stated above is true to the best of my information and belief.

Verified today, the.....day of.....2001.....

Signature of the authorised
representative, if any.

Signature of the applicant.

Notes.- (1) The form of memorandum of cross-objection and the form of certification shall, if the memorandum is filed by any person, other than the Commissioner of Central Excise be signed in accordance with the provisions of Rule 3.

(2) The memorandum of cross-objection shall be filed in quadruplicate.

Form No. E.A.-8

[See Rule 9]

Form of revision application to the Central Government under section 35EE of the Act

Revision application No.....of.....2001.....

1. Name and address of the applicant:
2. Address of the Commissioner (Appeals) passing the order against which the revision application is filed:
3. The number and date of the order:
4. Date of communication of the order:
5. Designation and address of the adjudicating authority against which the order has been passed by the Commissioner (Appeals):
6. Address to which notices/communications may be sent to the applicant:
7. Whether the appellant wishes to be heard in person.
8. (i) Description of classification of goods

- (ii) Period of dispute
 - (iii) Amount of duty, if any, demanded for the period mentioned in item (ii)
 - (iv) Amount of refund, if any, claimed for the period mentioned in item (ii)
 - (v) Amount of fine imposed
 - (vi) Amount of penalty imposed
 - (vii) Market value of seized goods.
9. Whether duty or penalty, if any, has been deposited (a copy/extract of the challan/account-current, as the case may be, under which the deposit is made, shall be furnished):
10. Relief claimed in application:

Statement of facts
Grounds of application

Signature of the authorised
representative, if any.

Signature of the applicant.

Verification

I,.....the applicant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Verified today, the.....day of.....2001.....

Signature of the authorised
representative, if any.

Signature of the applicant.

Notes.- (1) The grounds of application and the form of verification shall be signed by the person specified in sub-rule (2) of Rule 3.

(2) Where the application is signed by the authorised representative of the applicant, the document authorising the representative to sign and appear on behalf of the applicant shall be appended to the application.

(3) The application, including the statement of facts and the grounds of application shall be filed in duplicate and shall be accompanied by an equal number of copies of the order against which the application is filed and also the decision/order of the adjudicating authority against which Commissioner (Appeals) passed the order.

(4) The form of application shall be in English (or Hindi) and should set forth concisely and under distinct head grounds of application without any argument or narration and such grounds should be numbered consecutively.

(5) The fee of Rs. 200.00 required to be paid under the provisions of the Act shall be paid under T.R. 6 challan and the duplicate copy of the T.R. 6 challan shall be filed along with the application for revision.

[F. No. 354/66/2001-TRU]

T.R. RUSTAGI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2001

सं. 33/2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 447(अ).—केन्द्रीय सरकार, उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (मामलों का समझौता) नियम, 2001 है।
- (2) इनका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।
- (3) ये 1 जुलाई, 2001 को प्रवृत्त होंगे।

2. आवेदन का प्रकाश और रीति.—(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 32 (छ) की उपधारा (1) के अधीन आवेदन, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग को इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन, उसमें अंतर्विष्ट सत्यापन और ऐसे आवेदन के साथ लगे हुए सभी सुसंगत दस्तावेजों पर निम्नलिखित रूप में हस्ताक्षरित होंगे :—

- (क) व्यष्टि की दशा में, स्वयं उस व्यष्टि द्वारा या भारत में व्यष्टि के अनुपस्थित रहने पर संबद्ध व्यष्टि द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा; और व्यष्टि अप्राप्तवय होने पर या अपने मामलों को संभालने में मानसिक रूप से अक्षम होने पर उसके संरक्षक द्वारा या इसकी ओर से कार्यवाही करने के लिए सक्षम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा;
 - (ख) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में, कर्ता द्वारा और कर्ता के भारत में अनुपस्थित रहने पर या अपने मामलों को संभालने में मानसिक रूप से अक्षम होने पर उक्त परिवार के किसी अन्य वयस्क सदस्य द्वारा;
 - (ग) कंपनी या स्थानीय प्राधिकरण की दशा में, उसके प्रधान अधिकारी द्वारा;
 - (घ) फर्म की दशा में, उसके किसी भागीदार द्वारा, जो अप्राप्तवय नहीं है;
 - (ङ) किसी अन्य संगम की दशा में, संगम के किसी सदस्य या उसके प्रधान अधिकारी द्वारा; और
 - (च) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, उस व्यक्ति या उसकी ओर से कार्यवाही करने के लिए सक्षम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा।
- (3) प्रत्येक आवेदन चार प्रतियों में भरा जायेगा और उसके साथ एक हजार रुपए की फीस लगायी जायेगी।

3. मामलों के समझौता के लिए आवेदन में जानकारी का प्रकटन.—(1) समझौता आयोग, उक्त अधिनियम की धारा 32 च की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त से रिपोर्ट मांगते समय, नियम 2 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्रति, (उपाबंध, विवरण और ऐसे उपाबंध से संलग्न अन्य दस्तावेजों को छोड़कर) अग्रेषित कर सकेगा।

(2) उक्त अधिनियम की धारा 32 च की उपधारा (1) के अधीन, समझौता आयोग द्वारा आवेदन पर कार्यवाही के लिए आदेश किए जाने की दशा में, आवेदन के उपाबंध में अंतर्विष्ट जानकारी और विवरण तथा ऐसे उपाबंध से संलग्न अन्य दस्तावेज उक्त आदेश की प्रति के साथ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त को भेजी जायेगी।

4. संपत्ति की अंतिम कुर्की की रीति.—(1) उक्त अधिनियम की धारा 32 छ की उपधारा (1) के अधीन समझौता आयोग के आदेश किए जाने पर वह ऐसे आदेश की प्रति ऐसे स्थान पर अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त को भेजेगा जहां पर आवेदक के स्वामित्व की कोई जंगम या स्थावर संपत्ति स्थित है या वह निवास करता है या व्यापार करता है या उसका बैंक खाता है।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आदेश प्राप्त होने पर, आयुक्त अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त की श्रेणी से कम न हो, आवेदक की ऐसी संपत्ति की कुर्की के लिए कदम उठाने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) उपनियम (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी कुर्क संपत्ति की सूची तैयार करेगा और उसमें स्थावर संपत्ति की दशा में ऐसी संपत्ति का वर्णन जो उसकी पहचान के लिए पर्याप्त हो, विनिर्दिष्ट करेगा। और जमीन संपत्ति की दशा में उस स्थान को विनिर्दिष्ट करेगा जहां उक्त संपत्ति स्थित है या रखी गई है और उसकी एक प्रति आवेदक या ऐसे व्यक्ति को देगा जिसके भारसाधन से संपत्ति कुर्क की गई है।

(4) उपनियम (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी ऐसे तैयार की गई सूची की एक एक प्रति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त और समझौता आयोग को भेजेगा।

5. रिपोर्टों की प्रतियों के लिए फीस—कोई व्यक्ति जो उक्त अधिनियम की धारा 32 ज के अधीन किसी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है, प्रत्येक रिपोर्ट या उसके भाग के लिए प्रति पृष्ठ पांच रुपए की फीस का संदाय करेगा।

परिशिष्ट

प्ररूप सं. घ ग (ङ)-1

----- स्थित सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग ----- पीठ के समक्ष (उक्त अधिनियम की धारा 32 ङ के अधीन मामले के समझौता के लिए मामले का प्ररूप)।

1. आवेदन का पूरा नाम और पता :
2. पत्र व्यवहार के लिए पता :

3. (i) स्थायी लेखा सं. :
(ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रजिस्ट्रीकरण सं. :
(iii) प्रास्थिति :
4. आवेदक पर अधिकारिता रखने वाला केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त:
5. मामले/विवाद की अवधि/तारीख जिसके संबंध में समझौता के संबंध में आवेदन किया गया है :
6. क्या विवाद की अवधि के लिए उत्पाद, निकासी और संदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दर्शित करते हुए मासिक विवरणी फाइल की गई थी :
7. वे कार्यवाहियां जिनसे परिनिर्धारण के लिए आवेदन संबंधित है, वह तारीख जिसे कार्यवाहियां लंबित हैं और वह प्राधिकारी जिसके समक्ष कार्यवाहियां लंबित है :
8. ऐसी यथास्थिति अपील या पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाइल किये जाने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात्, जहां कोई अपील या पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया था, क्या ऐसी अपील या पुनरीक्षण मंजूर किया गया है :
9. अभिग्रहण की तारीख, यदि कोई है :
10. मामले के संक्षिप्त तथ्य और समझौता किए जाने वाले विवादों का विवरण :
11. विवाद में अंतर्वर्तित शुल्क की कुल रकम :
12. प्रकट किये गए और संदत्त किये जाने के लिए मंजूर किये गए शुल्क की अतिरिक्त रकम :

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्रीपत्नी.....निवासी.....सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मैं यह आवेदन.....के रूप में अपनी हैसियत से कर रहा हूँ और मैं इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

इस आवेदन की अंतर्वस्तु मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और मामले के तथ्यों से सुसंगत कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है। आवेदन से संलग्न दस्तावेजों के परिशिष्ट मूल प्रतियों की सत्य प्रतिलिपियां हैं और वित्तीय संव्यवहार दर्शाने वाली सारणियां सही हैं तथा सम्यक् रूप से मेरे द्वारा सत्यापित हैं।

आज तारीख.....2001 को.....में सत्यापित की गई।

(स्थान उल्लिखित करें)

अधिसाक्षी

टिप्पण :— 1. आवेदन फीस प्राधिकृत बैंक की शाखा या भारतीय स्टेट बैंक की शाखा या भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा में जमा कराई जानी चाहिए और चालान की तीसरी प्रति समझौता आयोग को आवेदन के साथ भेजी जाये। समझौता आयोग चैक, ड्राफ्ट, हुंडी या अन्य परक्राम्य लिख लें मंजूर नहीं करेगा।

2. कृपया बतायें कि आप व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का संगत आदि में से क्या है।

3. आवेदन के मद 12 में निर्दिष्ट, संदाय किये जाने के रूप में मंजूर की गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अतिरिक्त रकम इस आवेदन के उपाबंध में दी जायेगी।

उपाबंध

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अधिनियम, 1944 की धारा 32न (1) के अधीन किये गये आवेदन की मद 12 में निर्दिष्ट विशिष्टियों/विवरण —

1. जानकारी का, जिससे मासिक विवरणी में सही रूप में घोषित नहीं किया गया, ब्यौरा :—
2. मासिक विवरणी के अधीन आने वाले माल पर संदेय शुल्क की अतिरिक्त रकम और वह रीति जिसके द्वारा उक्त शुल्क प्राप्त हुआ;
3. जारी की गई कारण दर्शाओ सूचनाओं में, यदि कोई है, मांग किए गए शुल्क में से मंजूर किये गये शुल्क दायित्व और वह रीति जिससे उक्त शुल्क दायित्व प्राप्त किया गया ;
4. समझौता किये जाने वाले विवादकों से संबंधित तथ्यों की, जिसके अंतर्गत आवेदन द्वारा चाहे समझौता के नियंधन ही है ; पूर्ण और सही घोषणा।

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर

[फा. सं. 354/66/2001-टीआरयू]

टी. आर. रूस्तगी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2001

No. 33/2001-CENTRAL EXCISE (N. T.)

ॐ नमः शिवाय

G.S.R. 447(E).— In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title, extent and commencement.— (1) These rules may be called the Central Excise (Settlement of Cases) Rules, 2001.

(2) They extend to the whole of India.

(3) They shall come into force on and from the 1st day of July, 2001.

2. Form and manner of Application.— (1) An application under sub-section (1) of section 32E of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter referred to as the said Act), to the Customs and Central Excise Settlement Commission shall be made in the Form annexed to these rules.

(2) The application referred to in sub-rule (1), the verification contained therein and all relevant documents accompanying such application shall be signed,—

(a) in the case of an individual, by the individual himself or where the individual is absent from India, by the individual concerned or by some person duly authorised by him in this behalf; and where the individual is a minor or is mentally incapacitated from attending to his affairs, by his guardian or by any other person competent to act on his behalf;

(b) in the case of a Hindu undivided family, by the Karta and, where the Karta is absent from India or is mentally incapacitated from attending to his affairs, by any other adult member of such family;

(c) in the case of a company or local authority, by the principal officer thereof;

(d) in the case of a firm, by any partner thereof, not being a minor;

(e) in the case of any other association, by any member of the association or the principal officer thereof; and

(f) in the case of any other person, by that person or some person competent to act on his behalf.

(3) Every application shall be filled in quintuplicate and shall be accompanied by a fee of one thousand rupees.

3. Disclosure of information in the application for settlement of cases.— (1) The Settlement Commission may, while calling for a report from the Commissioner of Central Excise under sub-section (1) of section 32F of the said Act, forward a copy of the application referred to in sub-rule (1) of rule 2 (other than the annexure and the statement and other documents accompanying such annexure).

(2) Where an order under sub-section (1) of section 32F of the said Act, has been made to proceed with the application by the Settlement Commission, the information contained in the Annexure to the application and the statements and other documents accompanying such annexure shall be sent to the Commissioner of Central Excise along with a copy of the said order.

4. Manner of Provisional Attachment of Property.— (1) Where the Settlement Commission, orders attachment under sub-section (1) of section 32G of the said Act, it shall send a copy of such order to the Commissioner of Central Excise having jurisdiction over the place in which the applicant owns any movable or immovable property or resides or carries on his business or has his bank account.

(2) On receipt of the order referred to in sub-rule (1), the Commissioner may authorise any officer subordinate to him and not below the rank of an Assistant Commissioner of Central Excise to take steps to attach such property of the applicant.

(3) The officer authorised under sub-rule (2) shall prepare an inventory of the property attached and specify in it, in the case of the immovable property the description of such property sufficient to identify it and in case of the movable property the place where such property is lodged or kept and shall hand over a copy of the same to the applicant or to the person from charge the property is attached.

(4) The officer authorised under sub-rule (2) shall send a copy of the inventory so prepared each to the Commissioner of Central Excise and the Settlement Commission.

5. Fee for Copies of reports.- Any person who makes an application, under section 32J of the said Act, for obtaining copies of reports made by any Central Excise Officer, shall pay a fee of five rupees per page of each report or part thereof.

Appendix

Form No. SC (E)-1

Before the Customs and Central Excise Settlement Commission ----- Bench at ----- (Form of application for settlement of a case under Section 32E of the said Act)

1. Full Name and address of the applicant:
2. Address for communication:
3. (i)Permanent account no:
(ii)Central Excise registration no:
(iii)Status :
4. Commissioner of Central Excise having jurisdiction over the applicant:
5. Period / date of the cause / dispute in connection with which the application for settlement is made:
6. Whether monthly returns showing production, clearance and central excise duty paid were filed for the period of dispute:
7. Proceedings to which application for settlement relates, the date from which the proceedings are pending and authority before whom the proceedings are pending:
8. Where any appeal or application for revision has been preferred after the expiry of the period specified for filing such appeal or application for revision, as the case may be, whether such appeal or revision has been admitted:
9. Date of seizure, if any:
10. Brief facts of the case and particulars of the issues to be settled:
11. Total amount of duty involved in the dispute:
12. Additional amount of duty disclosed and accepted as payable:

Signature of the applicant.

Verification

I.....son/daughter/wife of.....residing atdo solemnly declare that I am making this application in my capacity as.....and I am competent to verify it.

That the contents of this application are true to the best of my knowledge and belief and no information relevant to the facts of the case has been suppressed. Annexures of the documents accompanying the application are true copies of the originals and the tables showing financial transaction are correct and are duly attested by me.

Verified today the.....day of.....(mention the month and year) at(mention the place)

Deponent.

Note: 1. The application fee should be credited in a branch of the authorised bank or a branch of the State Bank of India or a branch of Reserve Bank of India and the triplicate copy of the challan sent to the Settlement Commission with the application. The Settlement Commission will not accept cheques, drafts, hundies or other negotiable instruments.

2. Please state whether individual, Hindu undivided family, company, firm, an association of persons, etc.
3. The additional amount of Central Excise duty accepted as payable referred to in item 12 of the application shall be given in Annexure to this application.

Annexure

Statement containing particulars referred to in item 12 of the application made under section 32E(1) of the Central Excise Act, 1944

1. Details of information which has not been correctly declared in the monthly return:
2. Additional amount of duty payable on the goods covered in the monthly return and the manner in which such duty has been derived:
3. Duty liability accepted out of the total duty demanded in the show cause notice, if any, issued and the manner in which such duty liability has been derived:
4. Full and true disclosure of the facts regarding the issues to be settled including the terms of settlement sought for by the applicant.

Signature of the applicant

Place:

Date:

[F. No. 354/66/2001-TRU]
T. R. RUSTAGI, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 21 जून, 2001

अधिसूचना

सं. 34/2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 448 (अ).—केन्द्रीय सरकार, उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (उत्पाद शुल्क माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का हटाया जाना) नियम, 2001 है।

(2) इनका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) ये जुलाई, 2001 को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना—ये नियम उन विनिर्माता को लागू होंगे जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना का जिसके द्वारा उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने पर उत्पाद शुल्क माल (जिसे इसमें इसके पश्चात् विषयगत माल कहा गया है) को उपबंध 1 में दिए गए प्ररूप में 4 प्रतियों में आवेदन करेगा या तो किसी विशिष्ट परीक्षण की बाबत या तिमाही के लिए अपेक्षा की बाबत विषयगत माल की अनुमानित मात्रा और मूल्य और विषयगत माल की बाबत लागू होने वाली अधिसूचना की विशिष्टियां उपदर्शित होंगी।

3. फायदा अभिप्राप्त करने के लिए विनिर्माता द्वारा आवेदन (1) ऐसा विनिर्माता जो शुल्क की रियायती दर पर विनिर्दिष्ट उपयोग के लिए विषयगत माल प्राप्त करना चाहता है, यथास्थिति अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सहायक आयुक्त या उपायुक्त कहा गया है) को उपबंध 1 में दिए गए प्ररूप में 4 आवेदन करेगा।

(2) विनिर्माता विषयगत माल के प्रत्येक सप्लायर के मामले में अलग आवेदन करेगा।

(3) विनिर्माता एक साधारण बंधपत्र प्रतिभू या प्रतिभूति के साथ निष्पादित करेगा।

(4) बंधपत्र, उक्त सहायक समाहर्ता या उप समाहर्ता द्वारा उपयुक्त समझी गए रकम, जो किसी भी समय पर अनुमानित शुल्क देनदारी के समान हो, का होगा।

(5) आवेदन पर उक्त सहायक आयुक्त या उपायुक्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसमें यह प्रमाणित करेगा कि उक्त व्यक्ति ने विषयगत माल के अंतिम उपयोग की बाबत उसके समाधानप्रद रूप में एक बंधपत्र निष्पादित कर दिया है और ऐसे बंधपत्र की विशिष्टियां उपदर्शित करेगा।

(6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट आवेदन की चार प्रतियों में से एक प्रति विषयगत माल के विनिर्माता के रेंज अधिकक्षक को तथा दो प्रति विनिर्माता को दी जाएगी एवं एक प्रति उक्त सहायक आयुक्त या उपायुक्त द्वारा रखी जाएगी।

(7) उपनियम (6) के तहत विनिर्माता द्वारा प्राप्त आवेदन की एक प्रति, विषयगत माल के विनिर्माता को उक्त विनिर्माता द्वारा प्रेषित की जाएगी।

4. विषयगत माल के विनिर्माता द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया—(1) विषयगत माल का विनिर्माता नियम 3 के उपनियम (7) में निर्दिष्ट आवेदन के आधार पर छूट देने वाली अधिसूचना के फायदे का उपभोग करेगा।

(2) विषयगतमाल का विनिर्माता आवेदन पर हटाये जाने के ब्यौरे जैसे कि बीजक की संख्या और तारीख, विषयगत माल का वर्णन, मात्रा और मूल्य और रिहायती दर पर संदत्त उत्पाद शुल्क की रकम, अभिलिखित करेगा।

5. विषयगत की प्राप्ति के बारे में विनिर्माता द्वारा जानकारी का दिया जाना और अभिलेख रखा जाना विनिर्माता, विषयगत प्राप्त करते समय विषयगत माल की मात्रा और मूल्य, आशयित प्रयोजन के लिए उपभोग किए गए विषयगत माल की मात्रा, स्टॉक में बची हुई मात्रा, बीजकवार उपदर्शित करते हुए एक सामान्य लेखा रखेगा और उक्त सहायक या उपायुक्त को उपबंध II में दिए गए रिटर्न के प्रारूप में मासिक रिटर्न अलग महीने की दस तारीख तक प्रस्तुत करेगा।

6. कतिपय मामलों में शुल्क की वसूली,—

जहां विनिर्माता द्वारा विषयगत माल का उपयोग आशयित प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है वहां उक्त सहायक आयुक्त या उपायुक्त ऐसे विनिर्माता से ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क, यदि छूट न दी गई होती और विषयगत माल के विनिर्माता के कारखाने से हटाए जाने के समय पहले ही संदत्त शुल्क के बीच अंतर के समतुल्य रकम एवं ब्याज विनिर्माता द्वारा देय होगी तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) धारा 11क एवं 11कख के प्रावधान यथास्थिति ऐसी वसूली के लिए प्रभावी होंगे।

स्पष्टीकरण :—शंकाओं के समाधान के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि विषयगत माल आशयित प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया तब भी नहीं माना जायेगा जब विषयगत माल का कोई भाग खो जाये या प्राकृतिक कारण या परिवहन के दौरान दुर्घटना या विनिर्माता के परिसर में रख-रखाव के दौरान दुर्घटना में नष्ट हो जाये।

उपबंध 1

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (उत्पाद शुल्क माल के विनिर्माण के लिए शुल्क के रियायती दर पर माल का हटाया जाना) नियम, 2001 के अधीन आवेदन।

(मूल प्रति का 3 प्रतियों के साथ, रेंज अधिकक्षक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना)

सेवा में,

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या उपायुक्त,

प्रभाग.....

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 (1994 का 1) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) और तत्समय प्रयुक्त अन्य विधियों के सुसंगत उपबंधों के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5क (1) के अधीन सा.का.नि. के तहत जारी की गई अधिसूचना सं. उत्पाद शुल्क, तारीख को निम्नलिखित उत्पाद शुल्क (दरें विनिर्दिष्ट करें) मूल उत्पाद शुल्क/विशेष उत्पाद शुल्क/अतिरिक्त शुल्क/अन्य शुल्क लागू होता है।

हम उपर्युक्त अधिसूचना की अपेक्षानुसार यथाअपेक्षित (उत्पाद शुल्क माल के विनिर्माण के लिए शुल्क के रियायती दर पर माल हटाया जाना) नियम, 2001, का अनुसरण करने का वचन देते हैं। विषयगत माल की प्राक्कलित मात्रा और मूल्य जिसे हम उपर्युक्त विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान, अभिप्राप्त करना चाहते हैं, हैं (मात्रा और मूल्य विनिर्दिष्ट करें) और हम अपने पर स्थित परिसरों में उपयोग के लिए विषयगत माल प्राप्त करना चाहते हैं।

विषयगत माल पर उद्ग्रहणीय प्राक्कलित शुल्क, यदि उपरोक्त अधिसूचना के अधीन छूट नहीं मिली होती, केवल रूप है। (संगणित शीट संलग्न करें)

(क) — प्रयोजन के लिए विषयगत माल का उपयोग करने और किसी अन्य शर्त का जो उक्त अधिसूचना द्वारा हम पर अधिरोपित की जाए, अनुसरण करने का, और

(ख) पूर्वोक्त (क) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, विषयगत माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क यदि पूर्वांकत अधिसूचना के अंतर्गत छूट प्राप्त नहीं होती, और हटाए जाने के समय संदत्त के बीच अंतर के समतुल्य रकम का, मांग किए जाने पर संदाय करने का, वचन देते हैं।

हमने आप की स्वीकृति के लिए तारीख का आवश्यक बंधपत्र (निष्पादित बंधपत्र संलग्न करें) भी निष्पादित कर दिया है।

तारीख : प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम और परिसर के पते के साथ, हस्ताक्षर और स्टाम्प

स्थान :

(आवेदन पर उक्त सहायक आयुक्त या उपयुक्त से के पृष्ठांकन और प्रतिहस्ताक्षर)

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स ने जिनका परिसर में स्थित है, उक्त नियमों की अपेक्षानुसार द्वारा केवल रुपये के लिए बंधपत्र निष्पादित किया है जो अद्योहस्ताक्षरी द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से स्वीकार कर लिया गया है और बंधपत्र रजिस्टर के क्रम संख्याक तारीख पर प्रविष्ट कर लिया गया है।

फा. सं. उक्त सहायक या उपायुक्त के हस्ताक्षर, तारीख, नाम, स्टाम्प और मुद्रा सहित।

तारीख :

स्थान :

उपबंध II

मासिक रिटर्न (नियम 5 देखें)

विषयगत माल का नाम

क्रम सं.	विषयगत माल का वर्णन	विवरण			विनिर्मित माल			
		आरंभिक अतिशेष	प्राप्तियां	स्तंभ (3) और (4) का योग	आशयित प्रयोजन के लिए उपभुक्त मात्रा	अंतिम अतिशेष	प्रकृति	मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(6)	(7)	(8)	(9)

नोट :— हरेक प्रकार के उपयोग किए गए एवं विनिर्मित माल के लिए अलग प्रविष्टियां की जाएं।

मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैं/हम ने उक्त प्रविष्टियां मेरे/हमारे कारखाने में रखे गए रिकार्ड तथा किताबों से मिलान किया है एवं जहां तक हम जांच कर सके संपूर्ण है।

जांच

दिनांक :

स्थान :

विनिर्माता के हस्ताक्षर

नाम

मुद्रा सहित

[फा. सां. 354/66/2001-टीआरयू]

टी.आर. रूस्तगी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2001

No. 34/2001-CENTRAL EXCISE (N. T.)

G.S.R. 448(E).— In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) These rules may be called the Central Excise (Removal of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods) Rules, 2001.

(2) They extend to the whole of India.

(3) They shall come into force on and from the 1st day of July, 2001.

2. Application.- These rules shall apply to a manufacturer who intends to avail of the benefit of a notification issued under sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) hereinafter referred to as the Act) granting exemption of duty to excisable goods (hereinafter referred to as subject goods) when used for the purpose specified in that notification.

3. Application by the manufacturer to obtain the benefit.- (1) A manufacturer who intends to receive subject goods for specified use at concessional rate of duty, shall make an application in quadruplicate in the Form at Annexure I to the jurisdictional Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be (hereinafter referred to as the said Assistant Commissioner or Deputy Commissioner).

(2) The manufacturer shall make separate application in respect of each supplier of subject goods.

(3) The manufacturer shall execute a general bond with surety or security.

(4) The bond shall be for such amount as considered appropriate by the said Assistant Commissioner or Deputy Commissioner, to cover the recovery of duty liability estimated to be incurred at any given point of time.

(5) The application shall be countersigned by the said Assistant Commissioner or Deputy Commissioner who shall certify therein that the said person has executed a bond to his satisfaction in respect of end use of the subject goods and indicate the particulars of such bond.

(6) Of the four copies of the application referred to in sub-rule (5), one copy shall be forwarded to the jurisdictional range Superintendent of the manufacturer of the subject goods, two copies shall be handed over to the manufacturer and one copy shall be retained, by the said Assistant Commissioner or Deputy Commissioner.

(7) One copy of the application referred to in sub-rule (6) received by the manufacturer shall be forwarded by the said manufacturer to the manufacturer of subject goods.

4. Procedure to be followed by the manufacturer of subject goods. – (1) On the basis of the application referred to in sub-rule (7) of rule 3, the manufacturer of subject goods shall avail the benefit of the exemption notification.

(2) The manufacturer of the subject goods shall record on the application the removal details, such as No. and date of invoice, description, quantity and value of subject goods and amount of excise duty paid at concessional rate.

5. Manufacturer to give information regarding receipt of the subject goods and maintain records.- The manufacturer, receiving subject goods, shall maintain a simple account indicating the quantity and value of subject goods, the quantity of subject goods consumed for the intended purpose, and the quantity remaining in stock, invoice wise and shall submit a monthly return in Return at Annexure II to the said Assistant Commissioner or Deputy Commissioner by the tenth day of the following month.

6. Recovery of duty in certain cases.- Where the subject goods are not used by the manufacturer for the intended purpose, the manufacturer shall be liable to pay the amount equal to the difference between the duty leviable on such goods but for the exemption and that already paid, if any, at the time of removal from the factory of the manufacturer of the subject goods, alongwith interest and the provisions of section 11A and section 11AB of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) shall apply mutatis mutandis for effecting such recoveries.

Explanation.- For the removal of doubts, it is hereby clarified that subject goods shall be deemed not to have been used for the intended purpose even if any of the quantity of the subject goods is lost or destroyed by natural causes or by unavoidable accidents during transport from the place of procurement to the manufacturer's premises or during handling or storage in the manufacturer's premises.

Annexure I

Application under Central Excise (Removal of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods) Rules, 2001

(Original with 3 copies to be submitted through the Range Superintendent)

To,
The Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise,
Division

Vide S. No.....of Notification No.....Central Excise, dated theissued under Section 5A (1) of the Central Excise Act, 1944 read with the relevant provisions of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) and other laws for the time being in force the goods, namely,..... used for the specified purpose ofattract the following excise duty (ies) (specify rates): Basic excise duty /Special excise duty /Additional duty(ies) /Other Duty(ies).

We undertake to follow the Central Excise (Removal of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods) Rules, 2001 as required by the above notification. The quantity and value of subject goods, we wish to obtain during the financial year..... for the aforesaid specified purpose is.....(specify quantity and value) and we intend to procure the subject goods for use in our premises at.....

The estimated duty leviable on the subject goods but for the exemption under the above notification is rupees.....only (attach calculation sheet) and the estimated total duty on the subject goods payable at the time of removal under the above notification is rupeesonly (attach calculation sheet).

We also hereby undertake:

- (a) to use the subject goods for the purpose of and to follow any other condition that the said notification imposes on us; and

- (b) to pay on demand, in the event of failure to comply with (a) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the subject goods but for the exemption under the aforesaid notification and that paid at the time of removal.

We have also executed the necessary bond dated..... (enclose the bond executed) for your acceptance.

Date
Place

Signature and stamp of authorised signatory, with name and address of the premise

(Endorsement and counter-signature of the said Assistant Commissioner or Deputy Commissioner on the application)

It is hereby certified that M/shaving their premise at.... Have executed the bond as required by the said rules, for rupees....only, which has been accepted on behalf of the President of India by the undersigned and entered at S. No. datedof Bond Register.

F. No.

Signature of the said Assistant Commissioner or
Deputy Commissioner with date, name, stamp and seal

Date
Place

Annexure II
Monthly Return (See rule 5)

Name of subject goods

S.No.	Description of subject goods	Details				Closing balance	Goods manufactured	
		Opening balance	Received	Total of columns (3) & (4)	Quantity consumed for the intended purpose		Nature	Quantity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Note.- Separate entries should be made for each variety or class of goods used and manufactured.

I/We declare that I/we have compared the above particulars with the records (and) /books of my/our factory and that they are, insofar as I/we can ascertain complete.

Verified

Date :
Place:

Signature of manufacturer
Name in capital letters
Seal

[F. No. 354/66/2001-TRU]
T. R. RUSTAGI, Jt. Secy.

